

SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 12 | अंक : 246 | गुवाहाटी | शनिवार, 11 अप्रैल, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

रेगिस्तान में दिखी ब्रह्मास्त्र की ताकत, अपाचे ने किया...

पेज 2

असम विस चुनाव में युवाओं और महिलाओं की रही अहम भूमिका

पेज 3

मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 का किया उद्घाटन

पेज 5

हाँकी इंडिया ने टिम व्हाइट को भारतीय जूनियर महिला हाँकी टीम का ...

पेज 7

असम : एचएसएलसी परीक्षा में 65.62 प्रतिशत उत्तीर्ण

ज्योतिर्मय दास रहा टॉपर



गुवाहाटी (हि.स.)। असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को (एचएसएलसी) परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए, जिसमें कुल 65.62 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण रहे। परीक्षा में शामिल हुए 4,29,249 छात्रों में से 2,81,701 छात्र सफलतापूर्वक पास हुए। ये परीक्षाएं 10 से 27 फरवरी तक आयोजित की गई थीं, जबकि नतीजे 10 अप्रैल को घोषित किए गए। कुल 4,38,564 विद्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 9,315 अनुपस्थित रहे और 135 को परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निष्कासित कर दिया गया। पांच नतीजे रोक दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वालों में 1,86,468 छात्र और 2,42,781 छात्राएं थीं। प्रदर्शन के मामले में,

छात्रों का पास प्रतिशत 67.78 रहा, जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 63.96 रहा। डिबीजन वार आंकड़ों के अनुसार, 85,189 छात्रों ने प्रथम श्रेणी हासिल की, जिनमें से 3,983 ने डिस्टिंक्शन और 13,681 ने स्टार मार्क हासिल किए। कुल 1,50,167 उम्मीदवार द्वितीय श्रेणी में पास हुए, जबकि 46,345 ने तृतीय श्रेणी हासिल की। विभिन्न विषयों में 99,062 उम्मीदवारों ने लेटर मार्क हासिल किए। डिमा हसाओ 88.23 पास प्रतिशत के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर उभरा, जिसके बाद शिवसागर 84.08 प्रतिशत और डिब्रूगढ़ 78.46 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कछार जिले का पास प्रतिशत सबसे

-शेष पृष्ठ दो पर

वृंदावन में यमुना में मोटर बोट पलटने से पंजाब के 32 श्रद्धालु डूबे, 10 शव निकाले, तलाशी अभियान जारी

मथुरा। वृंदावन में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ है। पंजाब के श्रद्धालुओं का जत्था यमुना में घूमने के लिए मोटर बोट पर सवार हुआ था। यह बोट असंतुलित होकर पलट गई। नौ श्रद्धालुओं के शव निकाले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। मॉट थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर मोटर बोट पलट गई। इसमें पंजाब के मोगा, मुक्तेश्वर और लुधियाना से आए कुल 32 लोग सवार थे। इनके जत्थे में करीब 150 लोग शुक्रवार सुबह नौ बजे वृंदावन पहुंचे थे। सुबह निधिवन के दर्शन करने के बाद सभी



लोग यमुना में पर्यटन के लिए निकले थे। वृंदावन के केशीघाट पर सभी मोटर बोट पर सवार हुए। मॉट थाना क्षेत्र में बने पैटन पुल से मोटर बोट टकरा कर पलट गई। सभी 32 लोग डूब गए।

इनमें से नौ के शव निकाले गए। दस लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। गोताखोर लगातार डूबे लोगों को यमुना में खोज रहे हैं। घाट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया है। नदी में पानी का स्तर बढ़े होने से गोताखोरों को दिक्कत आ रही है। कई एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। गोताखोर श्रद्धालुओं को बाहर निकालने में जुटे हैं। घटनास्थल पर जागरण टीम में विनीत मिश्र व विपिन पाराशर मौजूद हैं। शाम साढ़े चार बजे तक नौ श्रद्धालुओं के

-शेष पृष्ठ दो पर

नीतीश कुमार हरिवंश ने ली रास की सदस्यता की शपथ

पवन खेड़ा को राहत, तेलंगाना एचसी ने दी अग्रिम जमानत

नई दिल्ली (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के निवर्तमान उपसभापति हरिवंश ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपगृहपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में उनको शपथ दिलाई। इस अवसर पर सदन के नेता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की ओर से दायर एफआईआर के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने दायर किया था। पवन खेड़ा ने उन पर कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (खेड़ा)



इस सप्ताह की शुरुआत में असम पुलिस ने दिल्ली स्थित उनके आवास की तलाशी भी ली थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया। खेड़ा की पैरवी कर रहे कांग्रेस नेता अभिषेक

को संबंधित कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाता है। खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस ने तब मामला दर्ज किया, जब उन्होंने यह दावा किया कि भुइयां के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं।

-शेष पृष्ठ दो पर

एआईएमआईएम ने हुमायूँ कबीर की पार्टी से तोड़ा गठबंधन

हैदराबाद (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के नेता हुमायूँ कबीर का एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने उनकी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का एलान किया है। एआईएमआईएम ने ऐसे बयानों पर चिंता भी व्यक्त की जो मुसलमानों की एकता पर सवाल उठाते हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में एआईएमआईएम की ओर से कहा गया है कि यूजेयूपी के नेता हुमायूँ कबीर के हालिया खुलासों ने बंगाल में



गठबंधन तोड़ दिया। एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का एलान किया है। एआईएमआईएम ने ऐसे बयानों पर चिंता भी व्यक्त की जो मुसलमानों की एकता पर सवाल उठाते हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में एआईएमआईएम की ओर से कहा गया है कि यूजेयूपी के नेता हुमायूँ कबीर के हालिया खुलासों ने बंगाल में

-शेष पृष्ठ दो पर

बंगाल के लिए भाजपा का घोषणापत्र : अमित शाह बोले- 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग, यूसीसी होगा लागू

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौर में हैं। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी किया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए इसे 'भरोसे का पत्र' बताया। पार्टी ने इसे सोनार बंगला का रोडमैप बताते हुए विकास, आश्वासन दिया कि बंगाल के ही बेटे को ही भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र राज्य के हर वर्ग की उम्मीदों



महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को

-शेष पृष्ठ दो पर

परिसीमन का मुद्दा गंभीर, महिला आरक्षण की आड़ में सरकार कर रही जल्दबाजी : कांग्रेस



नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की शुक्रवार को बैठक हुई। इसका उद्देश्य संसद के आगामी तीन दिवसीय अधिवेशन के लिए पार्टी की रणनीति बनाना

था। बैठक में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने विधायिका में महिलाओं के आरक्षण के साथ होने जा रहे परिसीमन को गंभीर मुद्दा बताते हुए सर्वसम्मति बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र की राजना सरकार राजनीति से प्रेरित होकर विधानसभा चुनावों के बीच में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक लाने जा रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक आज पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा

-शेष पृष्ठ दो पर

शिवमोग्गा में भूस्खलन, तीन मजदूरों की मौत, चार घायल

बंगलूरु। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में हुलिकल घाट पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां भूस्खलन की चपेट में आने से तीन मजदूरों की जान चली गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी। मृतकों की पहचान 37 वर्षीय राघवेंद्र, 30 वर्षीय राजू और 40 वर्षीय शब्बीर के रूप में हुई है। ये सभी मजदूर वहां सुरक्षा दीवार बनाने के काम में लगे थे। यह घटना गुस्वार दोपहर होसनगरा

-शेष पृष्ठ दो पर

बंगाल में बदल गया चुनावी गणित एसआईआर ने ममता के गढ़ में लगाई सेंध मतुआ वोट कटने से भाजपा की भी बड़ी चिंता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव एक बदले हुए चुनावी परिदृश्य में हो रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद करीब 90.83 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। इसकी वजह से कुल वोट संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ रह गई है। इस बड़े बदलाव ने टीएमसी और



अल्पसंख्यक और महिला वोटों की मजबूत मौजूदगी रही है, जिससे टीएमसी को अपनी

भाजपा दोनों के चुनावी गणित को प्रभावित किया है। टीएमसी की ताकत रहे जिलों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नदिया, मालदा, हुगली, हावड़ा, उत्तर दिनाजपुर और पूर्व बर्दवान में करीब 66.6 लाख नाम हटे हैं। इन क्षेत्रों में वोटों की वजह से कुल वोट संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ रह गई है। इस बड़े बदलाव ने टीएमसी और

-शेष पृष्ठ दो पर

देश में एलपीजी वितरकों और पेट्रोल पंपों के पास ईंधन के पर्याप्त स्टॉक : सुजाता शर्मा



नई दिल्ली (हि.स.)। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में एलपीजी वितरकों और पेट्रोल पंपों के पास ईंधन के पर्याप्त स्टॉक हैं। सरकार ने बताया कि किसी भी तरह की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। थरेल्यू रसीडेंट गैस यानी एलपीजी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है, जिसमें 98 फीसदी बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, जबकि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70 फीसदी तक बहाल हो गई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। सुजाता शर्मा ने बताया कि 14 मार्च से अब तक लगभग 1,06,000 टन कमर्शियल एलपीजी विक्रि हुई है और रोजाना 6,000 से 6,500

-शेष पृष्ठ दो पर

चार साल से लड़ रहे रूस-यूक्रेन ने किया संघर्षविराम का एलान

मॉस्को। भले यह अस्थायी संघर्षविराम हो, मगर एक ओर इरान-अमेरिका-इजराइल टकराव में आई अस्थायी शांति और दूसरी ओर रूस तथा यूक्रेन के बीच घोषित बर्तौस घंटे का संघर्षविराम दुनिया के लिए कुछ पलों का सुकून लेकर आया है। हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्धविराम शनिवार शाम चार बजे से शुरू होकर रविवार रात तक प्रभावी रहेगा।



बेलोसोव के माध्यम से सेना प्रमुख वालेरी गेरसिमोव को आदेश दिया है कि सभी दिशाओं संघर्षविराम देखा गया था, जो आरोप प्रत्यारोप के बीच दम तोड़ गया था।

में सैन्य कार्रवाई रोक दी जाए। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी उकसावे या आक्रामक कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सैनिक पूरी तरह तैयार रहेंगे। यानी यह शांति उतनी ही नाजुक है जितनी बारूद के ढेर पर रखी एक चिंगारी। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल भी इसी तरह का तीस घंटे का अल्पसंख्यक और महिला वोटों की मजबूत मौजूदगी रही है, जिससे टीएमसी को अपनी

-शेष पृष्ठ दो पर

ज्ञान को धन में परिवर्तित करने को तकनीक के साथ अनुसंधान भी जरूरी : गडकरी



नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि ज्ञान को धन में परिवर्तित के लिए नवाचार, विज्ञान तथा तकनीक के साथ-साथ कुशल कार्यबल और निरंतर अनुसंधान पर जोर देना आवश्यक है। गडकरी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद की ओर से यहां आयोजित 17वें सीआईडीसी विश्वकर्म पुरस्कार और प्रदर्शनी विकसित भारत 2047 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता से समझौता न करना और शॉर्टकट से बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवसरचका को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि तत्काल निर्णय लिए

-शेष पृष्ठ दो पर

असम विस चुनाव में युवाओं और महिलाओं की रही अहम भूमिका



गुवाहाटी (हि.स.)। असम में गुरुवार को आयोजित विधानसभा चुनाव में लगभग 86 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनावों की तुलना में अधिक है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुवाहाटी स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बार चुनाव में परिचित मतदाताओं की भागीदारी अधिक रही, जिसमें युवाओं और महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि इस बार लगभग 72 लाख मतदाता 30 वर्ष से कम आयु के थे, जिनमें करीब सात लाख मतदाताओं ने पहली बार अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने युवाओं के उत्साह और जिम्मेदारी की भावना की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। दिलीप सैकिया ने महिला मतदाताओं की बड़ी भागीदारी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के

युवावो इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत किया है और इसके लिए उन्होंने सभी महिलाओं का धन्यवाद किया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु के कई मतदाताओं ने घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाया, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के अनेक लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत यह दर्शाता है कि लोगों का लोकतंत्र में गहरा विश्वास है। सैकिया ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपेक्षा से अधिक सौंटे हासिल करेगा और राज्य में सरकार बनाना लगभग तय है।

करीमगंज नॉर्थ में पुनर्मतदान का आदेश 9 का मतदान रद्द

श्रीभूमि (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव 2026 के तहत करीमगंज नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 9 अप्रैल को संपन्न मतदान को चुनाव आयोग ने रद्द करते हुए पुनर्मतदान करने का आदेश दिया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2)(ए) के तहत आयोग ने प्राप्त रिपोर्टों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद मतदान केंद्र संख्या 239 - बेबीलैंड हाई इंग्लिश स्कूल पर हुए मतदान को अमान्य घोषित किया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने मतदान रद्द करने के सटीक कारणों का उल्लेख नहीं किया है। चुनाव आयोग ने उक्त मतदान केंद्र पर 11 अप्रैल (शनिवार) को पुनर्मतदान करने का निर्णय लिया है। मतदान का समय सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में पुनर्मतदान की व्यापक सूचना दी जाए तथा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को इसकी जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाए। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

असम एचएसएलसी परिणाम में विद्या भारती के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन



गुवाहाटी (हि.स.)। असम हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) परीक्षा 2026 में विद्या भारती के संबद्ध विद्यालयों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। शंकरदेव शिशु निकेतन, पटाचारकुची के मेधावी छात्र ज्योतिर्मय दास ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय और पूरे विद्या भारती परिवार का गौरव बढ़ाया है। विद्या भारती के विद्यालय असम में शिशु शिक्षा समिति, असम के माध्यम से तथा बरक घाटी

और डिमा हसाओ क्षेत्रों में शिक्षा विकास परिषद, दक्षिण असम के माध्यम से संचालित होते हैं। वर्तमान में राज्य में 576 विद्यालय मातृभाषा के माध्यम से मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रांतीय प्रचार संयोजक मुकुटेश्वर गोस्वामी ने बताया कि इस वर्ष एचएसएलसी परीक्षा में 403 विद्यालयों के 10,375 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इनमें से 5,623 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 3,546 ने द्वितीय श्रेणी तथा 516 ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की। इसके

अतिरिक्त 1,333 विद्यार्थियों ने लेटर मार्क्स हासिल किए, जबकि 383 विद्यार्थियों ने विशेष श्रेणी (डिस्टिंक्शन) प्राप्त की। समग्र परिणाम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि 164 विद्यालयों का परिणाम शत-प्रतिशत रहा, जबकि 17 विद्यालयों में सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उतीर्ण हुए। विद्या भारती के संस्थान शिक्षा के साथ-साथ असम की समृद्ध संस्कृति और भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले दो दशकों में विद्या भारती के आठ छात्रों ने राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। संस्था प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक पंचपदी शिक्षण पद्धति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। डॉ. पवन तिवारी, प्रो. गंगा प्रसाद परसाई, डॉ. जगदीन्द्र रायचौधुरी, कुलेंद्र कुमार भगवती, जगन्नाथ राजवंशी, महेश भगवत, निहारेंद्र धर तथा डॉ. दीपांकर पाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की। उल्लेखनीय है कि, पूर्व वर्षों में भी विद्या भारती के छात्रों ने राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिनमें ब्रह्म ठाकुरिया (2023), मेघाश्री बोरा (2019), मो. सरफराज हुसैन (2016), ज्ञानदीप शर्मा एवं स्तुति खॉंड (2012), प्रकाशज्योति कलिता (2011) तथा जुनाल तालुकदार (2010) शामिल हैं।

असम में चुनाव संबंधी झड़पों में करीब 30 लोग घायल हुए और सात गिरफ्तार किए गए



गुवाहाटी। असम में चुनाव से संबंधित हिंसा की अलग-अलग घटनाओं में करीब 30 लोग घायल हो गए और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाथारकांदी, मेरापानी और राहा जैसे इलाकों के मतदान केंद्रों पर प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच संक्षिप्त झड़पें हुईं। हालांकि, इन स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और यह सुनिश्चित किया कि मतदान बिना किसी बड़ी बाधा के जारी रहे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, श्रीभूमि जिले के पाथारकांदी निर्वाचन क्षेत्र में उस समय तनाव भड़क उठा जब कांग्रेस उम्मीदवार कार्तिक सेना सिन्हा कथित तौर पर रंगमती मतदान केंद्र में घुस गए और पीठासीन

अधिकारी से बहस करने लगे। सिन्हा का सीधा मुकाबला असम के मंत्री और भाजपा उम्मीदवार कुण्डु पॉल से है। इस झड़प में करीब 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए करीमगंज सिविल अस्पताल भेजा गया है कि पुलिस अधिकारी ने बताया। खबरों के मुताबिक, गडबड़ी के बाद बृथ पर मतदान लगभग तीन घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था और बाद में ईवीएम को बदलने के बाद फिर से शुरू हुआ। एक अलग घटना में, डिब्रूगढ़ जिले के खोंवांग निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा समर्थकों के साथ हुई हाथापाई में असम जातीय परिषद (एजेपी) के तीन नेता घायल हो गए। भाजपा ने आरोप

लगाया कि विधायक चक्रधर गोर्गोई के घर के पास स्थित एक निजी आवास में उसके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें प्रहलाद पांडे भी शामिल हैं, जो चुनाव प्रक्रिया में सहायता करने के लिए झारखंड से आये थे। चक्रधर गोर्गोई ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं कोई अलग-थलग घटना नहीं हैं, और दावा किया कि एक दिन पहले हलोधीबा में भी इसी तरह की घटनाएं घटी थीं। उन्होंने कहा कि गुरुवार की घटना के दौरान उनके कार्यालय को नुकसान पहुंचाया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। शिवसागर में एक अन्य घटना में, एक राजनीतिक दल के दो से तीन सदस्यों पर कथित तौर पर हमला किया गया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। शिवसागर सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे अखिल गोर्गोई ने आरोप लगाया है कि इस घटना के पीछे भाजपा उम्मीदवार कुशल डोवारी का हाथ है। सोशल मीडिया पोस्ट में गोर्गोई ने दावा किया कि दो लोग घायल हुए और वाहन क्षतिग्रस्त है। इसी बीच, कल रात तामुल्पुर जिले में भी हिंसा भड़क उठी। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य हाग्रामा मोहिलाने ने कहा कि बिस्मृत जांच से झड़प के कारणों का पता चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आगे की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

लुरिनज्योति गोर्गोई के आवास पर पुलिस की तलाशी

गुवाहाटी (हि.स.)। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद असम में असम जातीय परिषद (एजेपी) के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोर्गोई के आवास पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई खुमटाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरपथार गदापानी स्थित गोर्गोई के आवास पर की गई। पुलिस द्वारा यह तलाशी अभियान चलाने के पीछे के कारणों का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। लुरिनज्योति गोर्गोई के परिजनों ने आरोप लगाया है कि तलाशी के दौरान पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग और उत्पीड़न किया। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से घर में भय और तनाव का माहौल बन गया। हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले में आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

असम कांग्रेस ने सुरेन दैमारी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

गुवाहाटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की असम इकाई ने गुरुवार को अपने उदालगुड़ी उम्मीदवार, सुरेन दैमारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, एक दिन बाद जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने और चुनाव से हटने की घोषणा की थी। अपनी शिकायत में, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि दैमारी ने पार्टी का टिकट स्वीकार कर लिया था, चुनाव आयोग के मानदंडों के अनुसार अपना नामांकन दाखिल किया था और मतदान की पूर्ण संस्था पर अचानक पद छोड़ने से पहले पार्टी के चिन्ह के तहत सक्रिय रूप से प्रचार किया था। पार्टी ने दावा किया कि दैमारी ने कथित तौर पर *शरारती तत्वों* से प्रभावित होकर, अपने इस्तीफे की घोषणा करने से पहले कांग्रेस के खिलाफ गलत सूचना फैलाई। इसमें

आगे आरोप लगाया गया कि उम्मीदवार को चुनाव प्रचार से संबंधित खर्चों के लिए 30 लाख रुपये दिए गए थे और उन पर पार्टी के फंड का दुरुपयोग करने और संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, दैमारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व द्वारा उचित महसूस हुआ। उन्होंने दावा किया कि समर्थन मांगने के बार-बार प्रयास करने के बावजूद, उनके फोन का जवाब नहीं दिया गया और पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सहायता करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला इकाई ने भी समर्थन नहीं दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस

ने कहा कि दैमारी ने औपचारिक रूप से पार्टी को अपना इस्तीफा नहीं सौंपा था। इस बीच, चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इतने अंतिम चरण में नाम वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि समय सीमा पहले ही बीत चुकी है और उम्मीदवारों के नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर अंतिम रूप से दर्ज किए जा चुके हैं। मतदान कर्मियों को भी उनके संबंधित केंद्रों पर भेज दिया गया था, जिससे मतपत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना समाप्त हो गई थी। उदालगुड़ी सीट पर बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ), यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के उम्मीदवार भी मैदान में थे।

पवन खेड़ा पर एक्शन का सीएम हिमंत शर्मा ने किया बचाव, बोले- पुलिस अपना काम कर रही है

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में अपना कर्तव्य निभा रही थीं। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि हमने खेड़ा के पीछे पुलिस को लगाया है। हम और किसके लगाएंगे? उनके पीछे अल्फा नहीं, बल्कि पुलिस पड़ी है। अगर एफआईआर है, तो उस पर कार्रवाई करना

पुलिस का कर्तव्य है। हिमंत विश्व शर्मा ने आगे कहा कि पुलिस कानून की गुलाम है, और वे एक ऐसे व्यक्ति के घर जा रहे हैं जिसका नाम मामले में है, जो कानूनी है। पुलिस को अपराधियों के घरों में जाने के लिए ही वेतन मिलता है। ये टिप्पणियां तब आईं जब खेड़ा ने मुख्यमंत्री पर शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा से जुड़े आरोपों को लेकर उनके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। असम पुलिस ने शिकायत के बाद खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास की तलाशी ली

थी, लेकिन वे वहां नहीं मिले। शर्मा ने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोर्गोई पर भी निशाना साधा और उनके परिवार की श्रेष्ठता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गौरव गोर्गोई (जोरहाट में) अपनी मां के साथ वोट डालने गए थे, अपनी पत्नी के साथ नहीं। मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। अगर उनकी पत्नी उनके साथ जाती तो कितना अच्छा लगता। उन्होंने आगे कहा कि इससे भरे ये आरोप साबित होते हैं कि वो अपने परिवार को भारतीय नहीं बना सके।

मतदान रोककर मतदान केंद्र के भीतर पॉलिंग अधिकारी ने पढ़ा नमाज, व्यापक प्रतिक्रिया

बंगाईगांव (हि.स.)। असम के बंगाईगांव विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर पॉलिंग अधिकारी द्वारा केंद्र के भीतर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसके चलते कुछ समय के लिए मतदान प्रक्रिया रोक दी गई। यह घटना 59 नंबर बिजगांव जेबी स्कूल स्थित मतदान केंद्र संख्या 1 की बताई जा रही है, जहां पॉलिंग अधिकारी ने गुरुवार को मतदान केंद्र के अंदर नमाज पढ़ी। इस दौरान मतदान प्रक्रिया अस्थायी रूप से बाधित हुई। सूत्रों के अनुसार, कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो गई और मतदान फिर से शुरू कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर वहां कतार में खड़े मतदाताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं

दूसरी ओर, स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्कूल परिसर में एक नामधर तथा एक मंदिर स्थित है। ऐसे में इस स्थल पर नमाज पढ़ने से मंदिर की पवित्रता तथा सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को ठेस पहुंचेगी है। लोगों ने नमाज पढ़ने वाले

व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर, कई लोगों ने यह भी कहा कि मतदान की पूरी प्रक्रिया धर्मनिरपेक्षता के साथ संपन्न कराई जाती है। लोग अपनी-अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार घर से या अन्य स्थानों से पूजा-अर्चना करके मतदान केंद्र पर आते हैं।

मणिपुर में पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश

असम में 90 से अधिक सीटें जीतेगा भाजपा गठबंधन : सीएम



किया है। भाजपा मुख्यालय में बीती रात मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू बहुल क्षेत्रों के साथ-साथ अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में भी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। उन्होंने दावा किया कि इस बार असमिया पहचान की रक्षा के मुद्दे पर लोगों ने निर्णायक मतदान किया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गौरव गोर्गोई को इस चुनाव में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने गोर्गोई की राजनीतिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए उनके निजी और सार्वजनिक स्तर को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गुवाहाटी में मौजूद होने का दावा करने के बावजूद वे सुबह जल्दी ही राज्य छोड़कर चले गए। शर्मा ने कांग्रेस को *कार्यों की पार्टी* बताते हुए कहा कि उनके व्यवहार में कमजोरी झलकती है। अपने चुनावी अभियान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 300 से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं देवव्रत सैकिया और रिपुन बोरा पर सवाल उठाया कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर व्यापक प्रचार के लिए क्यों नहीं निकले।

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने विश्वास जताया है कि राज्य में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन 90 से अधिक सीटें हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार राज्यभर में मतदाताओं ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान किया है।

असम : एचएसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी

गुवाहाटी (हि.स.)। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशत में गत तीन दशकों में एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। यह 1994 में सिर्फ 30.9 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 2026 में 65.62 प्रतिशत हो गया है। ये आंकड़े राज्य की शिक्षा प्रणाली में लगातार हो रही प्रगति को दर्शाते हैं, जिसकी पहचान बेहतर बुनियादी ढांचे, उन्नत शिक्षण पद्धतियों और छात्रों की बढ़ती भागीदारी से होती है। जहां एक ओर कुल मिलाकर रुझान विकास की ओर इशारा करता है, वहीं ये आंकड़े समय-समय पर होने वाले उच्च उदार-चढ़ावों को भी दिखाते हैं जो नीतिगत बदलावों और असाधारण परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में, उत्तीर्ण प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा, जो 28.9 प्रतिशत और 38.7 प्रतिशत के बीच ही घुमता रहा। सबसे कम उत्तीर्ण दर 1997 में दर्ज की गई थी, जब केवल 28.9 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा पास की थी। हालांकि, 2000 के दशक की शुरुआत में लगातार सुधार की शुरुआत हुई और 2005 में उत्तीर्ण प्रतिशत पहली बार 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गया। 2011



और 2016 के बीच, परिणाम स्थिर रहे। आम तौर पर 60 प्रतिशत से ऊपर ही बने रहे। वर्ष 2013 में 70.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और शैक्षिक संसाधनों तक बेहतर पहुंच का संकेत था। इस प्रगति के बावजूद, 2017 में उत्तीर्ण प्रतिशत में भारी गिरावट आई और यह 47.9 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो हाल के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक थी। हालांकि, इसके बाद के वर्षों में परिणामों में

धीरे-धीरे फिर से सुधार होने लगा। 2021 में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया, जब उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़कर अभूतपूर्व 93.1 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था। शिक्षा विशेषज्ञ इस असाधारण उछाल का श्रेय कोरोना महामारी के दौरान अपनाई गई वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों और मूल्यांकन नीतियों को देते हैं, जब पारंपरिक परीक्षाएं बाधित हो गई थीं। महामारी के बाद, परिणाम फिर से अपने सामान्य स्तर पर लौट

आए। 2022 में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 56.4 प्रतिशत था, जो 2023 में बढ़कर 72.6 प्रतिशत हो गया और 2024 में 75.7 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो हाल के वर्षों में सामान्य परीक्षा स्थितियों के तहत सबसे ज्यादा है। 2025 में ये आंकड़े थोड़े घटकर 63.98 प्रतिशत हो गए, जिसके बाद 2026 में ये 65.62 प्रतिशत पर स्थिर हो गए, जो लगातार बेहतर प्रदर्शन की वापसी का संकेत है। शिक्षाविदों का कहना है कि यह समग्र सुधार सरकार की लगातार पहलों, ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा के विस्तार, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और माध्यमिक शिक्षा के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। पास होने के प्रतिशत में लगातार हो रही यह वृद्धि छात्रों की बेहतर तैयारी और संस्थागत सहयोग को भी दर्शाती है। शैक्षणिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जहां एक ओर दीर्घकालिक रुझान उदार-चढ़ाव लयांतर नीतिगत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। एक शिक्षा विशेषज्ञ ने टिप्पणी की कि आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि व्यवस्थागत सुधारों और सीखने के अनुकूल माहौल ने बेहतर परिणामों और योगदान दिया है। हालांकि, निरंतरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

इंफाल में पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश

इंफाल। मणिपुर में जारी तनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां छह युवकों को पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश और कर्फ्यू थोड़े घटकर 63.98 प्रतिशत हो गए, जिसके बाद 2026 में ये 65.62 प्रतिशत पर स्थिर हो गए, जो लगातार बेहतर प्रदर्शन की वापसी का संकेत है। शिक्षाविदों का कहना है कि यह समग्र सुधार सरकार की लगातार पहलों, ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा के विस्तार, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और माध्यमिक शिक्षा के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। पास होने के प्रतिशत में लगातार हो रही यह वृद्धि छात्रों की बेहतर तैयारी और संस्थागत सहयोग को भी दर्शाती है। शैक्षणिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जहां एक ओर दीर्घकालिक रुझान उदार-चढ़ाव लयांतर नीतिगत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। एक शिक्षा विशेषज्ञ ने टिप्पणी की कि आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि व्यवस्थागत सुधारों और सीखने के अनुकूल माहौल ने बेहतर परिणामों और योगदान दिया है। हालांकि, निरंतरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

संपादकीय

1600 ईरानी माताओं का दर्द कौन समझे?

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक मां की प्रार्थना से युद्ध की मानवीय पीड़ा उजागर हुई। अमेरिकी फाइटर पायलट के सकुशल वापसी से बाद से उस मां के चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन ईरान में अमेरिकी-इजरायली हमले में मारे गए 1600 से अधिक नागरिकों की माताओं का दर्द कौन समझे। सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक मां का संदेश आया। वह अपने फाइटर पायलट बेटे के लिए परेशान थीं। उन्होंने (पूर्व में टिवटर) पर लिखा - आज की रात प्रार्थनाओं में उन दो F-15 पायलटों को याद रखें, जिनके विमान ईरान में गिरा दिए गए हैं। मां साझा होती हैं और उनकी प्रार्थनाएं सभी पर असर करती हैं। अमेरिका ने तलाशी अभियान चलाकर अपने पायलट बचा लिए, उस मां के बेटे को भी। लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है, दूसरी तरफ ईरान की सैकड़ों मां आंसुओं में डूबी हैं। इस युद्ध में अब तक साढ़े तीन हजार से ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है। 1600 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं और करीब 250 बच्चे। संघर्ष के पहले ही दिन तेहरान के पास मिनाब में एक स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल गिरी, जिसमें सौ से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। ईरान की जिन मां ने अपने बच्चों को गंवाया है, क्या उनके दुख की कल्पना भी की जा सकती है! फिर पश्चिम एशिया के उन लोगों की भी सोचिए, जो बर्मा-मिसाइलों के धमाकों की दहशत में दिन-रात गुजार रहे हैं। कहीं यह युद्ध उन्हें हमेशा के लिए बदल न दे। अमेरिका और इजरायल इस युद्ध को जरूरी बता रहे हैं, पर यह झूठ है। युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता। हिंसा हमेशा प्रतिहिंसा को जन्म देती है, जिसमें मानवता की आहुति दी जाती है। युद्ध से फायदा होता है तो सिर्फ हथियार बेचने वाली कंपनियों को और उन सत्ताधीशों को, जो इसकी आड़ में राष्ट्रवाद का ज्वार बढ़ाकर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंसा का हमेशा इसलिए विरोध करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक, अगर इससे कुछ अच्छा दिखता भी है, तो वह अस्थायी होता है, लेकिन उसका चुरा असर स्थायी। युद्ध इसलिए भी कभी जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे छूट जाते हैं दुःख, प्रतिशोध, अशांति और तबाही। इनसे उबरने में बरसों लग जाते हैं। अगर रूस-यूक्रेन युद्ध की बात करें तो उसमें जितना नुकसान यूक्रेन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, उसे दोबारा खड़ा करने में करीब 600 अरब डॉलर लगेंगे। एक करोड़ यूक्रेनवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, 60 लाख तो देश ही छोड़कर चले गए। इस युद्ध ने भी कई माताओं की गोद सूनी कर दी है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने हमेशा शांति की वकालत की है।

कुछ

अलग

जिंदगी निगलती भीड़

पिछले दिनों वाराणसी में मोबाइल चोरी के संदेह में एक किशोर की पीट-पीट कर हत्या करने की हदयविदारक घटना सामने आई। घटना कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ही, साथ ही भीड़ की बर्बरता की कहानी भी कहती है। क्या एक बच्चे की जिंदगी मोबाइल से सस्ती है? सवाल समाज की बढ़ती आक्रामकता पर भी है। एक ओर हम समाज में कानून का शासन चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कानून हाथ में लेकर किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। निस्संदेह, यदि किसी व्यक्ति की अपराध में शामिल होने की आशंका भी है तो उसे पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अराजक तरीके से मार-पीटकर किसी की हत्या कर देने का अधिकार भीड़ को कैसे मिल सकता है? सवाल ऐसी घटनाओं पर शेष समाज की उदासीनता का भी है। जब उस किशोर को पीटा जा रहा था तो आसपास से गुजरने वाले लोग क्यों उसे बचाने नहीं आए? हाल के दिनों में महज शक के आधार पर लोगों को मौत के घाट उतारने व घायल करने की घटनाएं आम हो गई हैं। यह हमारे समाज के लिये भी चिंता का विषय है।

दृष्टि

कोण

खतरनाक मोड़ पर पहुंचा ईरान-अमेरिका युद्ध, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर

अमेरिका-इजरायल और ईरान संघर्ष अब सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमलों तक पहुंच गया है। पुल, रिफाइनरी और गैस सुविधाओं को निशाना बनाने से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। होमुज स्ट्रेट संकट से तेल कीमतें बढ़ने और वैश्विक महंगाई-मंदी का खतरा बढ़ गया है, जबकि शांति प्रयास जारी हैं।

अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से इतर अब पूरी तरह मूलभूत सुविधाओं को तबाह करने की तरफ मुड़ गई है। बीते 24 घंटे में दोनों पक्षों ने पुल, रिफाइनरी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। यह दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है।

तबाही की धमकी: अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बीते दिनों दावा किया कि उनकी ईरान की नई



रेजीम के साथ अच्छी बात चल रही है। फिर देश के नाम संबोधन में उन्होंने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी और अब शांति के प्रयासों से हटकर बात तबाही पर आ गई है। अमेरिका ने तेहरान के पास एक पुल पर बम गिराया, तो ईरान ने कुवैत और वअए में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधा। धमकी दी है कि

वह पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी असेट्स को बर्बाद कर देगा। फिर कैसे उबरेंगे: लेकिन इसमें नुकसान पूरी दुनिया का है। होमुज स्ट्रेट पर ईरानी नाकाबंदी की वजह से पहले ही लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई कम हो गई है। माना जा रहा है कि अगर जंग रुकती है, तो सप्लाई को फिर से सामान्य करने में कुछ महीने लग सकते हैं। लेकिन, अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए, तो उससे उबरने में कई साल लग जाएंगे।

नाकाफी होंगे इंतजाम: कुवैत, कतर और सऊदी अरब की ऑयल-गैस फैसिलिटीज और ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड को पहले ही इस युद्ध में काफी नुकसान पहुंचा है। कतर के ऊर्जा मंत्री शेरिडा अल-काबी ने तो पिछले महीने कहा था कि उनके देश की निर्यात क्षमता 17% तक कम हो सकती है। अभी देशों के पास अपना

स्ट्रैटिजिक रिजर्व है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अपील पर सदस्य देशों ने भी ऑयल रिजर्व रिलीज करने पर हामी भरी है। वहीं भारत ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम के दबाव से बचाने के लिए बीते दिनों एक्सहाइज ड्यूटी में कटौती की। लेकिन, अगर हमले जारी रहते हैं, तो सारे इमरजेंसी इंतजाम भी नाकाफी साबित होंगे। इस बीच, क्रूड ऑयल के 200 डॉलर प्रति बैरल तक जाने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं।

शांति का प्रयास: खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था तेल से जुड़ी है और उस तेल से कई देशों की अर्थव्यवस्था जुड़ती है। इसमें गड़बड़ी से मंदी और महंगाई की दोहरी मार पड़ेगी, जिसका असर भी दिखने लगा है। होमुज को खुलवाने के लिए कई देश मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यह तो जरूरी है ही, जल्द ही यह युद्ध भी रुकना चाहिए।

संसद का निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा

सब मिलकर करें नारी शक्ति को सशक्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी। 21वीं सदी की विकास यात्रा में भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह अवसर समानता, समावेशन और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के नए रूप में सामने आएगा। यह ऐसा समय है, जब संसद को एक ऐसा कदम बढ़ाना है, जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक एवं और अधिक प्रतिनिधिक बनाए। संसद का निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। यह क्षण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह तब आ रहा है, जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में असम में रोंगली विद्रो, ओडिशा में महा विश्वा पणा संक्रांति, पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी और केरलम में विष्णु पूरे उत्साह से मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुण्यांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत में बैसाखी का। मैं कामना करता हूँ कि ये दिव्य और पावन पर्व हम सभी के जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आएँ। इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियाँ हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की है। इन्होंने प्रेरणादायी अवसरों के बीच 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंका होगा। यह भारत की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षा का प्रतिबिंब है। हमारी नारी शक्ति लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उसने

राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारीशक्ति मिसाल बन रही है। साईंस एंड टेक्नोलॉजी, उद्यम, सशस्त्र बलों और खेलों के साथ हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं-बहनें और बेटियाँ देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं-बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी को मजबूती दी है, पर इन सारे प्रयासों के बावजूद राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी आफ गवर्नेंस में सुधार भी होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, संतुलित और उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास हुए। विधेयकों के मसौदे भी प्रस्तुत किए गए, पर वे पारित नहीं हो सके, फिर भी इस पर व्यापक सहमति रही कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा। अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और साथ ही विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराए जाएँ। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर संविधान की मूल भावना के साथ गहराई

से जुड़ा है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए। विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना इस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्र का भविष्य तय करने में प्रत्येक नागरिक को समान भूमिका हो। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। दशकों से इसकी आवश्यकता स्वीकार की गई है। अगर अब भी हम इसे टालते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि हम उस असंतुलन को और खींच रहे हैं, जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं। जब भारत पूरे आत्मविश्वास और हृदय संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब यह जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। इससे दशकों पुराना संकल्प पूरा होने के साथ विकास की गति बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने और भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह समय सामूहिक संकल्प का है। यह किसी एक सरकार, दल या व्यक्ति का नहीं, पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इसके महत्व को समझना है। महिला आरक्षण बिल पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं। वे भावी पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं और हमें बताते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत समय के साथ खुद को और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने की क्षमता में होती है। संसद का ऐतिहासिक सत्र करीब आ चुका है। मैं सभी दलों के सांसदों से नारीशक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूँ। आइए, हम अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

देश

दुनिया से

महिला आरक्षण से बदलेगा भारतीय लोकतंत्र का चेहरा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीति में कम हिस्सेदारी को सुधारने का प्रयास है। आबादी में लगभग आधी हिस्सेदारी के बावजूद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। लंबे इंतजार के बाद यह कानून लोकतंत्र को संतुलित बनाएगा, नीतियों में महिलाओं की आवाज बढ़ाएगा और राजनीति में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या में महिलाओं की आबादी 48.5% थी। अनुमान है कि पिछले करीब डेढ़ दशक में इसमें कुछ सुधार ही हुआ होगा, लेकिन जो नहीं बदला, वह है देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) इसी स्थिति को बदलने वाला कानून है और इसके पास व लागू होने में देरी नहीं होनी चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि राजनीति में महिलाएं महत्वपूर्ण तो रही, पर ज्यादातर वोट बैंक के नजरिये से। उनको उचित प्रतिनिधित्व आज भी नहीं मिल पाया है, जबकि हर क्षेत्र में समान अधिकार की बात की जाती है। मौजूदा लोकसभा में महज 14% महिला सांसद हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में तो स्थिति और खराब है - महज 10% महिला विधायक। और जब महिलाओं को मौका ही नहीं मिलेगा, तो यह सुधरेगा कैसे। भारत ने अपनी आजादी के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोटिंग



लंबे इंतजार के बाद यह कानून लोकतंत्र को संतुलित बनाएगा, नीतियों में महिलाओं की आवाज बढ़ाएगा और राजनीति में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या में महिलाओं की आबादी 48.5% थी। अनुमान है कि पिछले करीब डेढ़ दशक में इसमें कुछ सुधार ही हुआ होगा, लेकिन जो नहीं बदला, वह है देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) इसी स्थिति को बदलने वाला कानून है और इसके पास व लागू होने में देरी नहीं होनी चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि राजनीति में महिलाएं महत्वपूर्ण तो रही, पर ज्यादातर वोट बैंक के नजरिये से। उनको उचित प्रतिनिधित्व आज भी नहीं मिल पाया है, जबकि हर क्षेत्र में समान अधिकार की बात की जाती है। मौजूदा लोकसभा में महज 14% महिला सांसद हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में तो स्थिति और खराब है - महज 10% महिला विधायक। और जब महिलाओं को मौका ही नहीं मिलेगा, तो यह सुधरेगा कैसे। भारत ने अपनी आजादी के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोटिंग

का अधिकार देकर दुनिया के सामने नजरि पेश की थी, पर इसके अगले चरण - राजनीति में उनकी बराबर भागीदारी में देश पीछे रह गया। साल 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में पहली बार महिला आरक्षण बिल लाया गया था और तब से तीन दशकों में चार अस्फल प्रयास हो चुके हैं। अब सरकार ने बिल पास करने के लिए 16 से 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल में एक चुनावी रैली में महिलाओं से विपक्षी दलों पर दबाव बनाने की अपील की, ताकि संसद में महिला आरक्षण बिल बिना किसी विरोध के पास हो सके। आदर्श स्थिति तो यह होगी कि बिल को हर दल का साथ मिले, दबाव बनाने और विरोध की नौबत ही न आए। देर से ही सही, कम से कम अब इस काम को अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए।

जब सदन में ज्यादा महिलाएं होंगी, तो आधी आबादी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा आवाज मिलेगी। उनकी समस्याओं पर ज्यादा सटीक और संवेदनशील चर्चा हो सकेगी, जिससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। महिलाओं की अनगिनत उपलब्धियों के बावजूद राजनीति उन कुछ क्षेत्रों में है, जहां उन्हें बराबर मौके नहीं मिल पाते। महिला आरक्षण बिल इस कमी को दूर करेगा। इस बदलाव का असर पूरे समाज पर पड़ेगा। महिला आरक्षण का सवाल सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं, भारत के लोकतंत्र को और संतुलित व न्यायपूर्ण बनाने का मुद्दा है।

आप का

नजरीया

मालदा घटना से गरमाया बंगाल

मालदा की घटना और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। SIR को लेकर जनता में असंतोष, प्रशासनिक नाकामी और मतदाता सूची से नाम हटने के आरोपों से अविश्वास बढ़ा है। मालदा की घटना और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तलख टिप्पणी बताती है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के लिए परीक्षा बन चुका है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी है। इससे पहले जिस तरह के हालात बने हैं, उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बिल्कुल शुभ नहीं माना जा सकता।

मालदा के कालियाचक में भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। धेराव, लगातार विरोध-प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी घटनाओं से जाहिर है कि जमीनी स्तर पर लोगों में Special Intensive Revision (SIR) को लेकर गंभीर असंतोष है। हालांकि मालदा में उनके गुस्से ने कानून की सीमा को पार कर दिया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह घटना निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था की नाकामी का नतीजा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। राज्य में हालात लंबे समय से तनावपूर्ण हैं और पहले भी SIR ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को असुरक्षित स्थितियों का सामना करना पड़ा है। अगर जिम्मेदार अधिकारी हालात को गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पाए, तो यह उनकी नाकामी है। गौर करने वाली बात है कि चुनावों के ऐलान के बाद राज्य में ऊपर से नीचे तक बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले हुए हैं। जनता में अविश्वास। इस घटना के बीच जनता की चिंताओं को भी समझने की जरूरत है। बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले लगभग 7.6 करोड़ वोटर थे और अब करीब 10% कम हो गए हैं। फाइनल लिस्ट के बाद 60 लाख को तार्किक विसंगति में चिह्नित किया गया था। इनमें से अब तक 47 लाख आपत्तियों का निपटारा हो चुका है। हालांकि रिजेक्शन रेट बेहद ज्यादा बताया जा रहा है - 35 से 40% तक। लोगों का आरोप है कि उनके नाम काटे जा रहे हैं। इससे अविश्वास का माहौल है। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटने नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार नजर रखे हुए है और मामले के समाधान के लिए उसने SIR प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को लगाकर अभूतपूर्व रास्ता निकाला था।

मालदा की घटना और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तलख टिप्पणी बताती है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के लिए परीक्षा बन चुका है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी है। इससे पहले जिस तरह के हालात बने हैं, उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बिल्कुल शुभ नहीं माना जा सकता। मालदा के कालियाचक में भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। धेराव, लगातार विरोध-प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी घटनाओं से जाहिर है कि जमीनी स्तर पर लोगों में Special Intensive Revision (SIR) को लेकर गंभीर असंतोष है। हालांकि मालदा में उनके गुस्से ने कानून की सीमा को पार कर दिया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह घटना निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था की नाकामी का नतीजा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। राज्य में हालात लंबे समय से तनावपूर्ण हैं और पहले भी SIR ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को असुरक्षित स्थितियों का सामना करना पड़ा है।

उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी, प्रदेश में कुल 13.39 करोड़ मतदाता, 84 लाख मतदाताओं की हुई वृद्धि

लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) की लंबी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता हैं। इसमें 84 लाख 28 हजार 767 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इनमें प्रदेश में पुरुष मतदाता 7 करोड़ 30 लाख, 71 हजार 61 और महिला मतदाता 6 करोड़ 11 लाख 9525 हैं। तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 4 हजार 206 है। प्रदेश में 18 से 19 आयुवर्ग के मतदाताओं की कुल संख्या 17 लाख, 63 हजार 360 है। इसमें मतदाताओं में 54.54 प्रतिशत पुरुष जबकि 45.46 प्रतिशत महिला मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वे मतदाता अभी भी फॉर्म भेजकर सूची में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ समेत पांच जिलों में मतदाताओं की सर्वाधिक वृद्धि हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आज जारी की गयी अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश के पांच जिलों में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इनमें प्रयागराज टॉप पर है। प्रयागराज में 3 लाख 29 हजार 421 मतदाता, लखनऊ में 2 लाख 85 हजार 961 मतदाता, बरेली में 2 लाख 57 हजार 920 मतदाता, गाजियाबाद में 2 लाख 43 हजार 666 मतदाता और जौनपुर में 2 लाख 37 हजार 590 मतदाता बढ़े हैं। इसके अलावा प्रदेश के जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदाता वृद्धि दर्ज की गयी है। उनमें साहिबगढ़ में 82 हजार, जौनपुर में 56 हजार 158, लखनऊ पश्चिम में 54 हजार

822, फिरोजाबाद में 47 हजार 557 मतदाता बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि एसआईआर के तहत 6 जनवरी को 12.55 करोड़ मतदाताओं की मसौदा सूची जारी की गई थी। इसके बाद 6 मार्च तक लोगों से इस दृष्टिगत मतदाता सूची पर सभी प्रकार के दावे व आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी, इनमें 86.69 लाख लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए फॉर्म-6 भरा। वहीं 3.18 लाख लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए फॉर्म-7 भरा था। मतदाता सूची में 1.04 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके नाम का मिलान माता-पिता, बाबा-दादी व नाना-नानी से न होने के कारण इन्हें नोटिस दिया गया था। वहीं 2.22 करोड़ लोग तार्किक विसंगति वाले थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर में भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश व जिला स्तर पर बैठकें हुई हैं और उनमें आयी शिकायतें व जापानों की सुनवाई कर उनका त्वरित निराकरण किया गया, इतना ही नहीं इन दलों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, इन्होंने बूथ स्तर पर एसआईआर से जुड़े कार्यों को लेकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता में बताया कि प्रदेश में 166 दिन तक चली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। जारी मतदाता सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता हैं। इसमें 84 लाख 28 हजार 767 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इनमें प्रदेश में पुरुष मतदाता 7 करोड़, 30

बलिया में सीएमओ ने दस्तक अभियान का किया शुभारम्भ, बुखार के रोगियों की खोज करेंगी आशा

देवरिया (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में शुक्रवार को संचारी रोगों की रोकथाम के लिए दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने परशुराम चौक स्थित प्राथमिक विद्यालय से आशा, आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के साथ फीता काटकर तथा घर-घर दस्तक देकर अभियान को शुरूआत की। सीएमओ ने बताया कि यह अभियान

30 अप्रैल तक चलेगा। इसके तहत जिले की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर बुखार, खासी, जुकाम, मलेरिया, जेई/एड्स, चिकनगुनिया, क्षय रोग, फाइलेरिया और कालाजार जैसे लक्षणों वाले मरीजों की पहचान करेंगी। साथ ही कुपोषित बच्चों

की सूची भी तैयार की जाएगी। जिले में कुल 2756 आशा कार्यकर्ताओं की टीम सक्रिय है, जिन्हें प्रतिदिन कम से कम 15 घरों की स्त्रीनिंग का लक्ष्य दिया गया है। चिन्हित मरीजों का नवदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार कराया जाएगा। इस अवसर पर डिट्टी सीएमओ (वेक्टर बॉन डिजीज कंट्रोल) डॉ. हरेंद्र कुमार, अरबन नोडल अधिकारी डॉ. आरपी यादव, डीएमओ सीपी मिश्रा मौजूद रहे।

बागबेड़ा के सरकारी स्कूल में 80 बच्चों को मिला आयुष्मान भारत कार्ड

पूर्वी सिंहभूम (हि.स.)। पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा क्षेत्र स्थित नया बस्ती रोड नंबर-3 के एक सरकारी विद्यालय में शुक्रवार को एक सामाजिक एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 80 बच्चों के बीच भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और उनके अभिभावकों को आयुष्मान भारत योजना के लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि इस कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष लाखों रुपये तक का मुफ्त इलाज विभिन्न सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिल सकता है। इस अवसर पर पोस्टका की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने विद्यालय की रसोईया (मिड-डे मील कार्यकर्ता) को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने

संबोधन में कहा कि समाज के अतिम वृद्धि तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की भी सलाह दी। कार्यक्रम में भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान

साबित हो रही है और इससे स्वास्थ्य खर्च का बोझ काफी हद तक कम हुआ है। इस मौके पर भाजपा जिला मंत्री मनोज राम, भाजपा मुख्यालय प्रभारी सुबोध झा, बागबेड़ा के पूर्व तहसील अध्यक्ष धनन्जय उपाध्याय, संजय सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य पुनीत गिरी, उतपी बागबेड़ा की मुखिया गौरी टोपी, पूर्व मुखिया बुधराम टोपी, उपमुखिया मुकेश सिंह सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाजसेवी उपस्थित रहे।

रोहतास में जमीन घोटाले का बड़ा खुलासा! 26 एकड़ संपत्ति हड़पने का आरोप

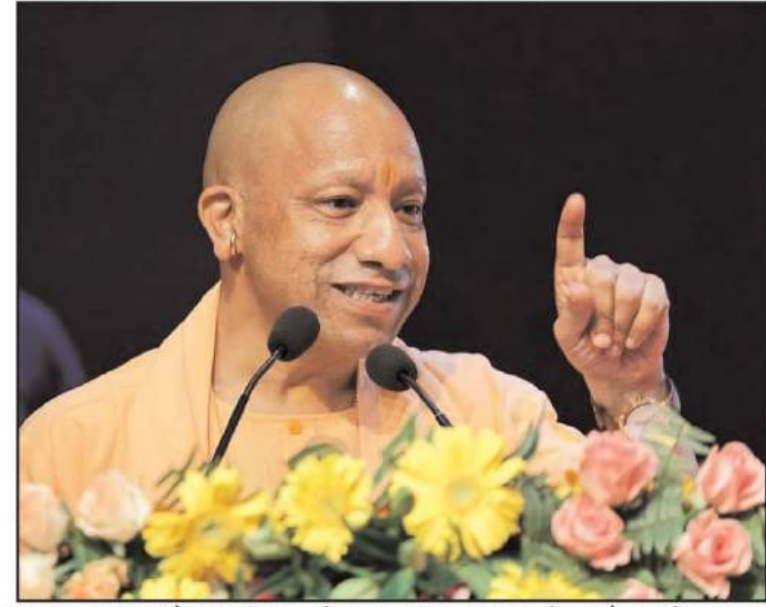
रोहतास (हि.स.)। बिहार में उपमुख्यमंत्री- सह राज्य मंत्री विजय सिन्हा की कोशिशों को उनके ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारी फिलता लगा रहे हैं। ताजा मामला रोहतास जिले के कोचस अंचल से जुड़ा है, जहां जमीन घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले के कोचस प्रखंड अन्तर्गत ग्राम सरेया में करीब 26 एकड़ पुरतनी संपत्ति को कथित साजिश के तहत राज्य अभिलेखों में छेड़छाड़ कर एक महिला और उसके बेटों के नाम दर्ज करा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी कटघरे में है। एक ही जमीन पर बार-बार जालसाजी, अदालत की टिप्पणी के बाद भी दोबारा खेल और अब सरकारी रिकॉर्ड का गायब होना सिस्टम पर गंभीर खाल खड़े करता है। ग्राम सरेया निवासी रजनीकांत तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्व माकण्डेय तिवारी की मौत के बाद उनकी संपत्ति पर उनकी पत्नी और तीन बेटियों का ब्याबर हक था। विधिवत दाखिल-खारिज के बाद वनों तक चारों के नाम से मालगुजारी रसीद भी कटती रही। शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2011 में पदमावती मिश्रा ने कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर के जरिए लोक अदालत सासाराम से

पूरी संपत्ति अपने नाम करने की कोशिश की थी। लेकिन, मामला खुलने पर 16 मार्च 2012 को लोक अदालत ने सखट टिप्पणी करते हुए डिग्री रद्द कर दी थी और कहा था कि अदालत को गुमराह कर आदेश हासिल किया गया। सबसे चौंका देने वाला आरोप यह है कि अदालत द्वारा जालसाजी उजागर होने के बावजूद उसी जमीन को दोबारा राज्य अभिलेखों में बदल दिया गया। आरोप है कि पदमावती मिश्रा ने अपने बेटों निखिल और राहुल के साथ मिलकर 26 एकड़ में से 19 एकड़ 23 डिसेमिल जमीन बेटों के नाम और शेष 6 एकड़ 78 डिसेमिल अपने नाम दर्ज करा ली। इस प्रक्रिया में बाकी दो बहनों का नाम पूरी तरह से रिकॉर्ड से हटा दिया गया और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। **म्यूटेशन फाइल गायब, आर्ट-1आई का जवाब भी नहीं- क्या छुपाया जा रहा है?** मामले की और संदिग्ध बनना है म्यूटेशन केस संख्या 455/16-17,

जिसके आधार पर जमीन ट्रांसफर होने की बात कही जा रही है। जब इसकी नकल मांगी गई तो अंचल कार्यालय ने लिखित में जवाब दिया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, सूचना के अधिकार (आर्ट-1आई) के तहत मांगी गई जानकारी भी तीन महीने बाद तक नहीं दी गई। जबकि कानूनन 30 दिन में जवाब देना अनिवार्य है। इससे पूरे मामले में पर्दा डालने की आशंका और गहरा गई है। खरीदार भी फंसे, म्यूटेशन पर रोकामामले का असर अब तीसरे पक्ष पर भी पड़ा है। बड़ी बहन आशा पाण्डेय द्वारा बेची गई जमीन के खर-दीवारों का म्यूटेशन भी अटका हुआ है। इससे वे कानूनी और आर्थिक संकट में फंस गए हैं। **बड़ा सवाल: बिना अधिकार बेटों के नाम कैसे हुई जमीन?** शिकायत में यह भी बड़ा कानूनी सवाल है कि मां के जीवित रहते निलाल को संपत्ति में बंटें का कोई सीधा अधिकार नहीं होता, फिर भी राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम कैसे दर्ज हो गया? **प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग - पीड़ित पक्ष ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, राज्य अभिलेखों में सुधार, वास्तविक हिस्सेदारों का नाम बहाल करके और इस कथित खेल में शामिल अधिकारियों व अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।**

मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 का किया उद्घाटन

लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काइयालॉजी सोसायटी ऑफ इण्डिया की ओर से लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में आयोजित नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भारत समेत कई देशों के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीमारू भारत सशक्त नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता और आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए इलाज से पहले लोगों को अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। इसके लिए चिकित्सकों को आगे आना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संस्था ने लंबी यात्रा तय करने के बाद यह सैमिनार लखनऊ में कर रही है। यह बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश का नया स्वरूप है। आज भारत नई प्रतिस्पर्धा के साथ दुनिया में खड़ा है। 2017 से पहले यह उत्तर प्रदेश खुद बीमारू राज्य के रूप में खड़ा था। आज भारत में अग्रणी भूमिका में खड़ा है। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में जहां प्राचीन काल से ही इन चीजों पर ध्यान दिया जाता रहा है। समय सोना, जगना, संतुलित आहार, फौटिक आहार लेना हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। यह सब हमारी दिनचर्या में शामिल था। दिनचर्या बदली, लाइफ स्टाइल बदली और उसके परिणाम भी हम सब के सामने हैं। आज हम सब जिस चुनौती से घिरे हुए हैं। इसके दो पक्ष हमारे सामने हैं। यह बचाव और



एक उपचार का पक्ष है। आपकी उपचार में रुचि में है। आप इस क्षेत्र में रिसर्च में रुचि होगी। लेकिन मेरा मानना है कि बचाव ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जागरूकता फैलाना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में इस बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम न उठाए हों। आठ से 10 साल पहले कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था तो परिवार को सबसे अधिक पैसे की चिंता होती थी। भारत के 60 से अधिक लोगों को हेल्थ स्कीम से जोड़ा गया है। उनका

यह प्रयास इलाज को सुलभ बनाएगा। इस सब के बावजूद यदि हमने अपने लाइफ स्टाइल नहीं बदलने से अच्छा जीवन मिल सकता है। मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को भीड़ है। क्या डॉक्टर अपने मरीज को पर्याप्त समय दे पा रहा है। चार से छह घंटे आम जन स्मार्ट फोन के सम्पर्क में है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग अपने दिनचर्या में बदलाव करें। इसके लिए यदि कोई चिकित्सक कहेगा तो उसकी बात लोग ज्यादा मानेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मिलावटखोरी चरम पर है। एक जिले में मैं गया था। उहाँ उपायद के बारे में जानकारी की। आप जितना चाहो उतना डेरी उत्पाद आर्डर कर दीजिए, वह सफाई कर देते हैं। छपा मरवाया तो हजारों कुंल खोया और पनीर बरामद हुआ। आज आप कार्यक्रम में जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो समझकर खा रहे हैं, वही है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी दिनचर्या में बदलाव कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दवाओं के साथ योग को आगे बढ़ाया। दुनिया उसे अंगीकार कर रही है। उपचार सस्ता हो, इस दिशा में सरकार ने कार्य किया है। भगवान की कृपा है कि गरीब को हृदय रोग कम ही होता है। वह कठिन परिश्रम करता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीमारू भारत सशक्त नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता और आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता है। चिकित्सकों से अपील किया कि वे दोनों पक्षों पर विचार करें। इस फील्ड के लिए अच्छा होगा ही, साथ में स्वस्थ समाज होगा। स्वस्थ समाज से ही देश स्वस्थ एवं समृद्ध होगा।

वाराणसी में पुलिस की सख्ती से कांग्रेसी पुतला दहन नहीं कर पाये

वाराणसी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर वाराणसी में शुक्रवार को कार्यकर्ता असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की तैयारी में थे। हालांकि, प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए कई

कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों को उनके घरों में ही रोक दिया। कांग्रेस के स्थानीय महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें साझा कर आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। महानगर अध्यक्ष के अनुसार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अमान के विरोध में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन प्रशासन ने पहले ही कार्रवाई करते हुए पार्टी के नेताओं के घरों के बाहर पहरा बैठा दिया।

वाराणसी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर वाराणसी में शुक्रवार को कार्यकर्ता असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की तैयारी में थे। हालांकि, प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए कई

कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों को उनके घरों में ही रोक दिया। कांग्रेस के स्थानीय महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें साझा कर आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। महानगर अध्यक्ष के अनुसार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अमान के विरोध में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन प्रशासन ने पहले ही कार्रवाई करते हुए पार्टी के नेताओं के घरों के बाहर पहरा बैठा दिया।

पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड : नक्सली राम मोहन सिंह मुंडा की जमानत याचिका खारिज

रांची (हि.स.)। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में 2016 से जेल में बंद नक्सली राम मोहन सिंह मुंडा की जमानत याचिका एनआईए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी। राम मोहन सिंह मुंडा उर्फ मोचू नक्सली साजिश रचने और हत्या मामले में आरोपित है। उल्लेखनीय है कि मामला बुंदू थाना कांड संख्या 65/2008 से जुड़ा है। 9 जुलाई 2008 को तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसकी जांच एनआईए की सौंपी गई थी। आरोपित राम मोहन सिंह मुंडा को 8 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। तब से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। एनआईए ने राम मोहन सिंह मुंडा को

23 नवंबर 2017 को एपूर्व (गवाह) बनाया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी अब गवाह बन चुका है। बयान पूरा हो चुका है और ट्रायल लंबा चल रहा है। वहीं एनआईए ने कहा कि कानून के अनुसार एपूर्व को ट्रायल खत्म होने तक हिरासत में रखना अनिवार्य है। मामले में पूर्व मंत्री राजा पीटर और कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन ट्रायल फेस कर रहे हैं।

किशनगंज में नाबालिग छात्रा का अपहरण, पड़ोसी युवक पर गुजरात ले जाने का आरोप



किशनगंज (हि.स.)। जिले के फरि-रंगोला क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर लगाया गया है। मामले को लेकर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने बच्ची की तलाश तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार फरि-रंगोला निवासी संजना कुमारी 7 अप्रैल को मध्य विद्यालय उठसा जाने के लिए एक ऑटो में सवार थीं, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों में उर-की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने संजना के मोबाइल की जांच की, जिसमें पता चला कि वह पड़ोस में रहने वाले रंजीत राय से लगातार बातचीत करती थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि

रंजीत राय ने संजना को बहला-फुसलाकर अपने साथ गुजरात ले गया है। इस संबंध में पीड़ित के पिता ने सदर थाना में लिखित आवेदन देकर रंजीत राय के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलते ही तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम छात्रा और आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। दोनों को लोकेशन ट्रेस करने के लिए तकनीकी सहायता ली जा रही है तथा गुजरात पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। दूसर, परिजनों ने पुलिस प्रशासन से जल्द बच्ची की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। उनका कहना है कि संजना लिखित रूप से स्कूल जाती थी, लेकिन अचानक लापता होने से परि-रवार चिंतित और भयभीत है।

बलिया में सातवीं चंद्रशेखर हाफ मैराथन का लोगो लांच, की गयी तैथरियों की समीक्षा

बलिया (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री जन्मदिन चंद्रशेखर की स्मृति में 19 अप्रैल को होने वाली सातवीं हाफ मैराथन का लोगो गुरुवार को देर शाम राज्यसभा सांसद नील शेखर ने अपने आवास 'झोपड़ी' पर चंद्रशेखर मैराथन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में लांच किया। इस अवसर पर अब तक की गयी तैथरियों की समीक्षा भी की गयी। पटपर (पंचखोरा) स्थित शारदा पेट्रोल पंप से जिला मुख्यालय स्थित वीर लोरीक स्पोर्ट्स स्टेडियम तक 2.1 किमी दूरी वाले इस मैराथन की

हुई। काफी देर तक चर्चा के बाद आयोजन समिति से जुड़े सभी सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गयी। आयोजन समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद नील शेखर ने कहा कि चंद्रशेखर हाफ मैराथन की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री की गरिमा और वैश्विक खिलाड़ियों के आगमन को देखते हुए इस बार के आयोजन को भव्य रूप देना है। चंद्रशेखर मैराथन समिति के सचिव उषेंद्र सिंह ने पूरे आयोजन की फररखा सबके सामने प्रस्तुत किया।

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने फर्जी निकासी मामले में सभी जिलों से मांगी वित्तीय निकासी की जांच रिपोर्ट

रांची (हि.स.)। झारखंड में पुलिस कार्यालयों से संदिग्ध वित्तीय निकासी का मामला सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय से शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों और इकाइयों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह कदम प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट में बोकोरो पुलिस कार्यालय से वेतन मद में अनियमित भुगतान उजागर होने के बाद उठाया गया है। मुख्यालय की ओर से रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एसएसपी, सभी जिलों के एसपी, विभिन्न पुलिस इकाइयों के समाष्ट, रेंज डीआईजी और जौनल आईजी को प्र भेजकर अपने-अपने कार्यालयों में हुई वित्तीय निकासी की जांच करने को कहा गया है। साथ ही वित्त और गृह विभाग के स्तर से प्राप्त रिपोर्टों का हवाला देते हुए रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार बोकोरो एसपी कार्यालय से मई 2024 से दिसंबर 2025 के बीच वेतन मद में करीब 3.15 करोड़ रुपये का भुगतान संदिग्ध पाया गया है। वहीं समीक्षा के दौरान हजारीबाग एसपी कार्यालय से

भुगतान करने की बात भी सामने आई है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कई मामलों में स्वीकृत वेतन से अधिक राशि का मासिक भुगतान किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में निचले स्तर के लिपिकीय कर्मचारियों से लेकर वरीय अधिकारियों तक की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय को आशंका है कि इसी तरह की अनियमितताएं अन्य जिलों में भी हो सकती हैं, इसलिए सभी इकाइयों से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

सीवान सिविल कोर्ट फिर निशाने पर: बम धमकी से दहशत, जांच में निकली फर्जी साजिश

सीवान (हि.स.)। सीवान जिले के सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से शुक्रवार को पूरे न्यायिक परिसर में अफरा-तफरी मच गई। ईमेल के जरिए दी गई इस धमकी ने प्रशासन की नींद उड़ा दी और कुछ ही मिनटों में पूरा कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। धमकी भरा मेल प्रधान जिला बम संचालनालय मोतीश कुमार के आधिकारिक ईमेल पर आया, जिसमें सुबह 11:30 बजे कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही एसपी पूरन कुमार झा और डीएम विवेक रंजन मैथव्य हरकत में आए और तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। देखते ही देखते बम स्व्यायड, डॉग स्व्यायड और फायर ब्रिगेड की टीमों के चपे-चपे की सघन तलाशी ली गई। हर आने-जाने वाले व्यक्ति की कड़ी जांच की गई और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया। घंटों चली जांच के बाद भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे साफ हो गया कि धमकी फर्जी थी।

बम-बार धमकी, प्रशासन के लिए सिरदर्द - यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 28 जनवरी को निशाना बरामद करने के लिए आरिफर कौन है जो न्यायिक व्यवस्था को निशाना बनाकर उर का माहौल बनाना चाहता है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की तैयारी की जा रही है।

टाटा पंच सीएनजी को सुरक्षा परीक्षण में मिली उच्चतम रेटिंग



नई दिल्ली

कार निर्माता स्वदेशी कंपनी टाटा पंच सीएनजी को हाल ही में सुरक्षा परीक्षण में उच्चतम रेटिंग प्राप्त हुई है। यह कार उन परिवारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरी है, जो कम बजट में अपने प्रियजनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते। भारत एनकेप द्वारा किए गए सुरक्षा परीक्षण में टाटा पंच को पूरे 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो इसे देश की सबसे सुरक्षित किफायती सीएनजी कारों में शामिल करती है।

यह कार वयस्कों के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए भी उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। कंपनी ने हर संस्करण में 6 एयरबैग्स जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल किए हैं, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाते हैं। कठोर परीक्षण के

दौरान एक भारी वाहन से टक्कर के बाद भी, गाड़ी का मुख्य कबिन सुरक्षित रहा, जो इसकी मजबूत संरचना का प्रमाण है। उच्च संस्करणों में चारों ओर देखने वाला कैमरा, ब्लाईड व्यू मानिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण और टायर दबाव निगरानी प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलती हैं, जो ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाती हैं।

टाटा मोटर्स की इस लोकप्रिय कार का सीएनजी विकल्प लगभग 6.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है, जिसका सड़क पर उतरने वाला मूल्य करीब 7.70 लाख रुपये है। इसके उच्च संस्करण लगभग 9.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाते हैं। इस कीमत श्रेणी में इतनी उच्च सुरक्षा देने वाली कार उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है।

विप्रोफिर लाएगा शेयर बायबैक, तीन साल बाद बड़े फैसले की तैयारी

मुंबई। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड एक बार फिर शेयर बायबैक पर फैसला लेने जा रही है। करीब तीन साल बाद कंपनी इस विकल्प पर विचार कर रही है, जिससे निवेशकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। विप्रो ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक 15 और 16 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी, जिसमें इविटी शेयरों के बायबैक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि यह प्रक्रिया कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी के बायबैक नियम 2018 के तहत पूरी की जाएगी। कंपनी के पास तीसरी तिमाही तक करीब 57,394 करोड़ रुपये का कैश रिजर्व है, जो उसे इस तरह के बड़े फैसले लेने में सक्षम बनाता है। विप्रो पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच अपने मुनाफे का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शेयरधारकों को लौटाएगी। ऐसे में बायबैक इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2023 में 12,000 करोड़ रुपये का बायबैक किया था, जिसमें शेयर 223 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए थे। 2020 और 2019 में भी कंपनी इस तरह की पहल कर चुकी है। खास बात यह है कि विप्रो आमतौर पर बाजार भाव से 16 से 19 प्रतिशत प्रीमियम पर शेयर खरीदती रही है।

7-सीटर कार के खरीदारों के लिए कई किफायती विकल्प मौजूद

नई दिल्ली
भारतीय बाजार में वर्तमान में 7-सीटर कार के खरीदारों के लिए कई किफायती विकल्प मौजूद हैं, जो शहर और हाईवे दोनों पर आरामदायक सफर देते हैं। इस लिस्ट में निसान ग्रावित, रिनाल्ट ट्रीबर, महिंद्रा बोलोरो, महिंद्रा बोलोरो नीयो और माहूति इटिंगा जैसे माडल शामिल हैं। निसान ग्रावित इस सेगमेंट की सबसे सस्ती 7-सीटर एमपीवी मानी जा रही है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 5.65 लाख रुपये है।



MOST AFFORDABLE 7-SEATERS

महिंद्रा की 7-सीटर एमपीवी मराजो को नहीं मिले ग्राहक

नई दिल्ली। मार्च 2026 में महिंद्रा की 7-सीटर एमपीवी मराजो को एक भी ग्राहक नहीं मिला। मराजो एमपीवी का पिछले तीन महीनों से खता नही खुला है। दिसंबर 2025 में इसकी आखिरी बार 80 युनिट बिकी थीं, जिसके बाद से इसकी बिक्री पूरी तरह टप है। जानकारी के मुताबिक, कंपनी अब इसके बचे हुए स्टॉक को खाली करने में जुटी है, हालांकि यह एमपीवी अभी भी कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.06 लाख रुपये से लेकर 16.38 लाख रुपये तक हैं। मराजो की साल 2025 की बिक्री के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी में शून्य, फरवरी में 17, मार्च में 10, अप्रैल में 6, मई में 4, जून में 17, जुलाई में 176, अगस्त में 46, सितंबर में 3, अक्टूबर में 2, नवंबर में 47 और दिसंबर में 80 युनिट्स बिकी। इस तरह पूरे साल में इसकी कुल 408 युनिट्स ही बिक पाई, जिससे इसकी मासिक औसत बिक्री मात्र 34 युनिट्स रही। शार्क-प्रेरित डिजाइन वाली इस एमपीवी में 7 और 8 सीटर का विकल्प मिलता है। यह 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, जो 121 हासपावर की ताकत और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबाक्स, 7-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, एबीएस और ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन ये सभी विशेषताएं भी इसकी गिरती बिक्री को रोक नहीं पा रही हैं। साल 2026 की शुरुआत भी मराजो के लिए निराशाजनक रही, जनवरी, फरवरी और मार्च में इसे एक भी ग्राहक नहीं मिला।



इसमें माइयूएल सीटिंग, रियर एसी और अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो इसे शहर के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। वहीं रिनाल्ट ट्रीबर भी लगभग इसी कीमत पर उपलब्ध है और अपनी वर्सेटाइल सीटिंग व बेहतर माइलेज के कारण लंबे समय से लोकप्रिय बनी हुई है। अगर मजबूत और एफ-टफ एक्सप्लूरी की तलाश है तो महिंद्रा बोलोरो एक भरोसेमंद विकल्प है, जो खराब सड़कों पर भी शानदार प्रदर्शन देती है। वहीं महिंद्रा बोलोरो नीयो उसी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा माडर्न फीचर्स और बेहतर कम्पर्ट के साथ आती है। दूसरी ओर माहूति इटिंगा फैमिली कार के रूप में सबसे संतुलित विकल्प मानी जाती है। इसमें ज्यादा स्पेस, बेहतर माइलेज और कम रनिंग कास्ट मिलती है, साथ ही सीएनजी विकल्प इसे और किफायती बनाता है। कुल मिलाकर, कम बजट में 7-सीटर कार खरीदने वालों के लिए ये पांचों माडल अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं। बला दें कि देश में बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर कार हमेशा पहली पसंद होती है, खासकर जब बजट सीमित हो और साथ में स्पेस, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद परफॉर्मंस की जरूरत हो।

भारत का ई-रिटेल बाजार 66 अरब डालर के पार



मुंबई। भारत का आनलाइन खुदरा बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। 2025 में ई-रिटेल का आकार 65-66 अरब डालर तक पहुंच गया है, जिसमें मजबूत उपभोग और डिजिटल पहुंच का बड़ा योगदान रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-रिटेल बाजार 2025 में 65-66 अरब डालर के सकल व्यापार मूल्य (जीडीपी) तक पहुंच गया है। यह सालाना आधार पर 19-21 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी दरों में कटौती, आयकर में राहत, घटती महंगाई और काम ब्याज दरों के चलते निजी खर्च में भी सुधार हुआ है। 2022-24 के दौरान जहां यह वृद्धि 8 प्रतिशत थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पांच साल पहले तक भारत का ई-रिटेल सेक्टर संभारनाओं पर आधारित था, लेकिन अब यह मजबूत हकीकत बन चुका है। सक्रिय आनलाइन खरीदारों की संख्या करीब 30 करोड़ तक पहुंच गई है और विक्रेताओं का नेटवर्क तीन गुना बढ़ा है। इस ग्रोथ में महानगर शहरों और जेन जेड की अहम भूमिका रही है। जेन जेड अब ई-रिटेल ग्राहकों का 40-45 प्रतिशत हिस्सा बन चुका है। वहीं, टियर-2 और उससे छोटे शहरों में 2025 के दौरान आनलाइन आर्डर में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि इन क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच अभी भी 25-30 प्रतिशत के बीच है।

ग्लोबल मार्केट से पाजिटिव संकेत, एशिया में भी तेजी का रुख

नई दिल्ली
पश्चिम एशिया में शांति वार्ता के एक बार फिर पटरी पर लौटने की खबर से दुनिया भर के बाजार का मूड सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और इजरायल तथा ईरान के बीच जारी जंग के थमने की उम्मीद की वजह से बाजार में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स स्पूचर्स भी मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार चौतरफा मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं।
पश्चिम एशिया में जारी जंग के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही कोशिश के कारण अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान उसाह का माहौल बना रहा, जिसकी वजह से चाल स्ट्रॉट के सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 275.88 अंक यानी 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 48,185.80 अंक तक पहुंच गया। इसी तरह एफ एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,824.66 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डैक 186.66 अंक यानी 0.82 प्रतिशत उछल कर 22,821.66 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, डाउ जॉन्स स्पूचर्स फिलहाल 0.03 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 48,200.25 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है।
अमेरिकी बाजार के विपरीत यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 10,603.48 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

सर्चा बाजार में फिसला सोना, चांदी की भी घटी चमक

नई दिल्ली

घरेलू सर्चा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट का रुख नजर आ रहा है। सोना गुरुवार के शुरुआती कारोबार की तुलना में 2,170 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,360 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। इसी तरह चांदी की कीमत में भी कल के शुरुआती कारोबार की तुलना में 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक की कमजोरी दर्ज की गई है। सोने की कीमत में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्चा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,51,470 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,38,840 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। इसी तरह चांदी के भाव में तेजी आने के कारण ये चमकाली धातु दिल्ली सर्चा बाजार में 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,51,620 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,990 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,51,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,38,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,51,520 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। इसी तरह शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,51,620 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,38,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्चा बाजार में भी सोने के भाव में कमजोरी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,51,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,38,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त मजबूती नजर आ रही है।



इस तेजी के कारण टोक्यो का निककेई इंडेक्स 936.68 अंक यानी 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 56,832 अंक के स्तर पर आ गया है। इसी तरह ताइवान का ताइवान वेड इंडेक्स 418.06 अंक यानी 1.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 35,279.22 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.83 प्रतिशत की छलांग लगा कर 1,502.08 अंक के स्तर पर, हंग सेंग इंडेक्स 211.60 अंक यानी 0.82 प्रतिशत उछल कर 25,964 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.63 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,991.14 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

ग्लोबल मार्केट से पाजिटिव संकेत, एशिया में भी तेजी का रुख

नई दिल्ली
पश्चिम एशिया में शांति वार्ता के एक बार फिर पटरी पर लौटने की खबर से दुनिया भर के बाजार का मूड सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और इजरायल तथा ईरान के बीच जारी जंग के थमने की उम्मीद की वजह से बाजार में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स स्पूचर्स भी मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार चौतरफा मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं।
पश्चिम एशिया में जारी जंग के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही कोशिश के कारण अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान उसाह का माहौल बना रहा, जिसकी वजह से चाल स्ट्रॉट के सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 275.88 अंक यानी 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 48,185.80 अंक तक पहुंच गया। इसी तरह एफ एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,824.66 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डैक 186.66 अंक यानी 0.82 प्रतिशत उछल कर 22,821.66 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, डाउ जॉन्स स्पूचर्स फिलहाल 0.03 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 48,200.25 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है।
अमेरिकी बाजार के विपरीत यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 10,603.48 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

273.64 अंक यानी 1.15 प्रतिशत फिसल कर 23,806.99 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद की वजह से एशियाई बाजार में भी जोश नजर आ रहा है। एशिया के सभी नौ बाजार के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफटी 105.50 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,989.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेंस टाइम्स इंडेक्स 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,982.82 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है।
जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स ने जोरदार छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 148.42 अंक यानी 2.03 प्रतिशत उछल कर 7,456.01 अंक के स्तर पर पहुंच चुका है। इसी तरह कोम्पो इंडेक्स 101.40 अंक यानी 1.75 प्रतिशत की उछल के साथ 5,879.41 अंक के स्तर पर आ गया है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त मजबूती नजर आ रही है।
इस तेजी के कारण टोक्यो का निककेई इंडेक्स 936.68 अंक यानी 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 56,832 अंक के स्तर पर आ गया है। इसी तरह ताइवान का ताइवान वेड इंडेक्स 418.06 अंक यानी 1.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 35,279.22 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.83 प्रतिशत की छलांग लगा कर 1,502.08 अंक के स्तर पर, हंग सेंग इंडेक्स 211.60 अंक यानी 0.82 प्रतिशत उछल कर 25,964 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.63 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,991.14 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

इसी तरह सीएम्सी इंडेक्स ने 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,245.80 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएस इंडेक्स

न्यूज़ ब्रीफ

अंतरिक्ष यात्री करेंगे चंद्रमा पर वीडियो रिकार्ड

नई दिल्ली। अपने महत्वाकांक्षी अर्टेमिस-2 मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक कंज्यूमर स्मार्टफोन आईफोन 17 प्रो मैक्स को शामिल किया है। अर्टेमिस-2 मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाकर सुरक्षित वापस लाना है। इस मिशन में ऑरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए चंद्रमा की परिक्रमा की जाएगी, जो भविष्य में मानव को चंद्रमा पर वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह पहली बार है जब किसी लोकप्रिय स्मार्टफोन को डीप स्पेस मिशन में आधिकारिक रूप से इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। इस मिशन में आईफोन को किसी मुख्य सिस्टम के रूप में नहीं, बल्कि सहायक उपकरण के तौर पर शामिल किया गया है। अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग फोटो और वीडियो रिकार्डिंग के लिए कर रहे हैं, ताकि अंतरिक्ष अनुभव को अधिक व्यक्तिगत और वास्तविक तरीके से कैद किया जा सके। हालांकि, किसी भी सामान्य डिवाइस को अंतरिक्ष में भेजने से पहले कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। माइक्रोप्रिविटी के माहौल में उपकरणों को टूटने या तेरने का खतरा रहता है, इसलिए आईफोन को विशेष माउंट्स और वेल्डों के जरिए सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा, सुरक्षा कारणों से इसमें इंटरनेट और ब्लूटूथ जैसी सुविधाओं को निष्क्रिय कर दिया गया है। मिशन में निकोन डी5 और गोप्रो हीरो 11 जैसे प्रोफेशनल कैमरा भी मौजूद हैं, लेकिन आईफोन को अतिरिक्त डिवाइस के रूप में शामिल किया गया है।

अमेरिका जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, व्यापार समझौते की संभावना

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए इस महीने के अंत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन का दौरा करेगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका ने फरवरी में एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य आपसी व्यापार बढ़ाना, बाजार पहुंच को आसान बनाना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। अब इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता की तैयारी है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिगन ग्रीर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह इस महीने के अंत में वाशिंगटन पहुंचने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने और प्रस्तावित व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए उत्सुक है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही विश्व सचिव समूह मिसरी ने वाशिंगटन में भारत-अमेरिका व्यापार सुविधा पोर्टल का शुरुआत की।

आपूर्ति संकट और मध्य पूर्व तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

मुंबई। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में शुक्रवार को फिर तेजी देखने को मिली, जब नू-राजनीतिक तनाव और आर्थिकों की अशांति ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका-ईरान सीजफायर को लेकर अनिश्चितता, मध्य पूर्व में सैन्य तनाव और प्रमुख समुद्री मार्गों पर जोखिम के कारण तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। ब्रेट क्रूड 1.13 प्रतिशत बढ़कर 97.01 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि वेस्ट टेक्सस इंटरमीडियेट (ब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.39 प्रतिशत बढ़कर 99.24 डालर प्रति बैरल पर टैड करता नजर आया। भारत के मल्टी कम्पोजिट एक्सचेंज पर भी असर दिखा, जहां 20 अप्रैल डिलीवरी वाला क्रूड आयाल फ्यूचर्स करीब 2.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 9,150 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया। बाजार में यह तेजी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर स्पष्टता नहीं है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के साथ-साथ सऊदी अरब के ऊर्जा डॉन के बीच शिपिंग मार्गों पर अशांति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रिपोर्टों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से शिपिंग गतिविधियां सामान्य स्तर से काफी कम हो गई हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई पर दबाव बना है। मध्य पूर्व में इजरायल और लेबनान के बीच जारी तनाव ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया है।

घर हो या ऑफिस, झपकी लेना बॉडी को जॉर्ज करने जैसा है। सिर्फ 15 से 20 मिनट की झपकी ही आपको फ्रेश कर देगी जिससे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी और दिमाग को नए-नए आइडियाज भी मिलते हैं। हेल्थ को मॉडर्न करने के लिए 7-8 घंटे की नींद परफेक्ट होती है लेकिन इस्टेट एनर्जी के लिए झपकी लेना भी बेस्ट ऑप्शन है। स्ट्रेस कम करता है: काम करने के दौरान महज 10-20 मिनट की झपकी लेकर आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। रिसर्च में पाया

20 मिनट की झपकी रखेगी सेहत को चुस्त-दुरुस्त

गया है कि उन लोगों में स्ट्रेस हॉर्मोन का लेवल बहुत ही कम होता है जो काम के दौरान बीच-बीच में झपकी से खुद को रिलेक्स करते रहते हैं। इतना ही नहीं झपकी (पावर नैप) लेने के बाद से माइंड दोगुनी स्पीड से काम करता है। एनर्जी बढ़ता है: रात को ठीक से नहीं सोने की वजह से अगर दिन में नींद आ रही है और उस वक्त सोना पॉसिबल नहीं तो

पावर नैप इसका एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नींद आने के बावजूद भी माइंड को एक्टिव रखने की कोशिश करना दिमाग पर पर बुरा असर डालता है। वहीं 20 मिनट की झपकी लेने से बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो दोबारा काम करने के लिए एक्टिव हो जाती है। हार्ट को हेल्दी रखता है: झपकी लेना सिर्फ माइंड ही नहीं पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है। इससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों के होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है।

आंखों के लिए अमृत है विटामिन ए

इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए आंखों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उसकी रोशनी चली जाए तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इसलिए हमें अपनी आंखों की सेहत के लिए खासकर विटामिन ए पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दरअसल विटामिन ए हमारी आंखों को तो स्वस्थ रखता ही है, हमारी त्वचा, बाल, नाखून, दांत, हड्डियों आदि के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है।



जब सहाब जाए दर्द

स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए हम तमाम जतन करते हैं, लेकिन आज की जीवनशैली में कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफें देबे पांव हमारे पास आ ही जाती हैं। ऐसी ही तकलीफों में शामिल है दर्द। कुछ दर्द तो ऐसे होते हैं, जो हमें छोड़ते ही नहीं। इन्हें डॉक्टरों की भाषा में क्रॉनिक पेन कहा जाता है।

तमाम जतन के बाद भी कुछ दर्द ठहर जाते हैं। महीनों चले इलाज में हमें यह भ्रम जरूर होता है कि अब यह दर्द लौट कर नहीं आएगा, लेकिन तब तक दर्द अपनी नींव और मजबूत कर चुका होता है। दुनियाभर की दवाएं, इंजेक्शन, शारीरिक थेरेपी आदि कराने का

कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टरों की भाषा में ऐसे दर्द को 'क्रॉनिक पेन' यानी स्थाई दर्द कहते हैं, जो समय के साथ जाता नहीं, रुक जाता है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक चार भारतीय महिलाओं में से एक और हर दस में एक पुरुष को क्रॉनिक दर्द की समस्या है। हमारे देश में

यह समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन साथ निभाने वाली इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा, कोई तो उपाय ऐसे होंगे, जिनकी सहायता से जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को हमेशा के लिए अलविदा कहना आसान होगा। आज उन्हीं रास्तों के बारे में बात करते हैं।

दिमाग और दर्द

कई महीनों तक एक ही स्थान पर हो रहे दर्द के हम धीरे-धीरे आदी हो जाते हैं। इलाज होने के बाद भी हम उस जगह के दर्द को लेकर सचेत रहते हैं और हमें दर्द महसूस होने लगता है। मनोचिकित्सकों की मानें तो कभी-कभी वास्तव में दर्द न होते हुए भी हम किसी खास जगह पर दर्द महसूस करने लगते हैं। जिस तरह थकान न होने पर भी यदि हम ऐसा महसूस करें तो थकान महसूस होने लगती है।

जब सताए जोड़ों का दर्द

हम में से हर चौथा व्यक्ति जोड़ों के दर्द से परेशान है। तेज भागती जिन्दगी की रफ्तार के बीच देबे पांव यह कब आ जाता है, पता नहीं चलता। हड्डियों के विशेषज्ञ के मुताबिक जोड़ों के दर्द की शुरुआत में ही हमें सचेत हो जाना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार शुरुआती दौर में ही यदि हम नियमित व्यायाम करें और उपचार कराए तो दर्द से राहत मिल जाती है। लेकिन दर्द पुराना हो जाए तो उसे उपचार और व्यायाम से ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें सर्जरी करानी पड़ सकती है। हालांकि सर्जरी सबसे आखिरी स्थिति है, लेकिन कई बार बोन रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है।



ऐसे रखें जोड़ों का खयाल

काम करने का तरीका बदलें: हम में से अधिकांश लोग कंप्यूटर के सामने घंटों काम करते हैं, लेकिन अपने बैठने के तरीकों पर ध्यान नहीं देते। कुर्सी पर बैठते हुए हमारी पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपकी कुर्सी बहुत नीचे न हो। इसके अलावा अगर आप काफी देर तक टाइप करते हैं तो अपनी अंगुलियों को थोड़ा आराम दें, क्योंकि काफी देर

तक टाइपिंग की वजह से आपकी अंगुलियों में दर्द का ठहराव हो सकता है। अगर संभव हो तो अपने घुटनों को कमर से ऊपर रखें। इसके लिए आप पैरों के नीचे कुछ रख सकते हैं। **थोड़ा आराम भी है जरूरी:** जोड़ों में दर्द खासकर कमर का दर्द लगातार काम करने की वजह से बढ़ जाता है, इसलिए शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। हमारी हड्डियों की क्षमता की एक सीमा है। उससे ज्यादा समय तक काम करने

पर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इनका आराम करना भी उतना ही जरूरी है। **गुनगुने पानी में डुबो कर रखें:** मांसपेशियों और हड्डियों को राहत देने में गुनगुना पानी कारगर साबित होता है। दिनभर के काम के बाद कुछ देर शरीर को गुनगुने पानी में डुबो कर रखें। इससे मांसपेशियों और हड्डियों में नई ऊर्जा का संचार होगा और दर्द से आराम मिलेगा।

योग और व्यायाम करें

हड्डियों को सपोर्ट देने वाली मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए योग और व्यायाम की सहायता ली जा सकती है। योग और व्यायाम काफी हद तक हमें कई बीमारियों से दूर रखते हैं। इसके अलावा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ते हैं।

डॉक्टरों की सलाह

- घुटनों में या दूसरे जोड़ों में बहुत दर्द हो तो उन पर ज्यादा जोर न डालें, इससे स्थिति और खराब हो सकती है।
- किसी भी चमत्कारी दवा का इस्तेमाल न करें। कई बार चमत्कारी दवा के नाम पर लोग धोखा करते हैं।
- खाने-पीने का खास ध्यान रखें और खाने में दूध और अंडे को शामिल करें।
- सिर्फ उसी व्यायाम या योग को आजमाएं, जिसमें जोड़ों पर बहुत ज्यादा जोर न पड़ता हो।

हेल्दी खाएं

हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम सबसे उपयोगी माना जाता है। उन्हीं जगहों में रहने वालों को तो सॉलिमेंट के तौर पर विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक हमारी हड्डियों के आसपास एक खान किस्म का तरल पदार्थ होता है, जिसकी वजह से वे घुमती और मुड़ती हैं। जैसे-जैसे यह तरल पदार्थ कम होता है, हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ता है। इस तरह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और धीरे-धीरे घिसने लगती हैं। इसलिए इनका संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर ओमेगा-3 फैटी एसिड लेने की सलाह देते हैं। मछली में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी के लिए धूप और कैल्शियम के लिए दूध सबसे अच्छा स्रोत है।

ऐसे चलता है दर्द का चक्र

- दर्द शुरू होता है।
- आपकी सक्रियता कम हो जाती है।
- डॉक्टर के पास जाते हैं।
- टेस्ट कराते हैं और कई सारी दवाएं लेते हैं।
- दर्द में राहत मिलता है।
- आप ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं।
- पहले से ज्यादा दर्द महसूस करते हैं।
- सक्रियता और कम हो जाती है।
- बड़े डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है।
- ताकत में कमी पाते हैं।
- पहले की तरह सक्रिय न रहने की वजह से निराशा होती है।
- आखिरकार आपकी मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं।

सहयोग ही है सबसे बड़ा इलाज

शुरुआती दौर में डिमेंशिया की स्थिति में परिवार रोगी की मनोदशा व स्थिति को उभार कर मान अनदेखा करता है। यह उपेक्षा सहन न करने के कारण रोगी विरोध का सा माहौल बना लेता है और इमोशनल ट्रांजा की अवस्था बन जाती है। हालांकि ऐसे में न्यूरोलॉजिस्ट काउंसलिंग कराने की सलाह देते हैं। सबसे बड़ा और कारगर इलाज है घर वालों का सहयोग। जो रोगी है, वह अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन घर वाले जानें कि यह बीमारी है और उन्हें इसमें पूरा सहयोग कर न केवल रोगी की स्थिति सुधारने में मदद करें, बल्कि यहां-वहां घूम कर व्यर्थ पैसा व श्रम बेकार न करें। जितनी जल्दी यह रोग पहचाना जाए, उतना ही अच्छा है। समय पर इलाज कराने से रोगी की स्थिति नियंत्रण में रहेगी। इलाज के दौरान लगने वाला समय अत्यंत लंबा हो सकता है, इसलिए परेशान न हों। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परिवारजनों की है, क्योंकि वे ही सबसे पहले स्वभाव में आए परिवर्तनों को देख पाते हैं। रोगी की सही देखरेख और आत्मियता उसके लिए मददगार हो सकती है।

दिमागी कसरत है फायदेमंद

अल्जाइमर जैसे रोग को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का योगदान महत्वपूर्ण है। डॉक्टर इस बीमारी का इलाज करते हैं न दूध पाए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमागी कसरत इस बीमारी को दूर रख सकता है। नई भाषा सीखें, गेम, डांस, संगीत और खेलों में समय लगाएं।

डाइट जो अल्जाइमर पर रखे नियंत्रण

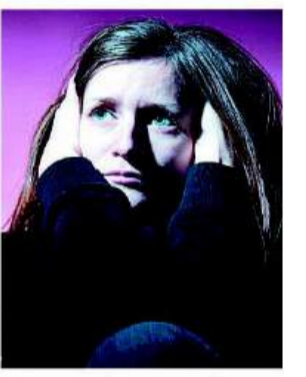
ब्रेकफास्ट महत्वपूर्ण है शोध बताते हैं कि सुबह का नाश्ता दिन भर की एनर्जी के लिए जरूरी है। हेल्दी नाश्ते से दिमाग को ईंधन मिलता है। इससे याददाश्त इंगुव होती है व एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन ज्यादा कैलोरी वाला खाना आपको आलसी बनाता है और एकाग्रता में कमी लाता है।

चीनी कम

चीनी दिमाग को ईंधन देने का काम करती है, लेकिन टेबल शुगर नहीं, बल्कि खाने से मिला ग्लूकोज। तभी अत्यंत लो फील होने पर एक गिलास मीठा पेय आपको फर्तीला बना देता है। एनर्जी बूस्टर का काम करता है कार्बोहाइड्रेट और शुगर। मधुमेह के शिकार हैं तो डाइटिशियन की सलाह लें।

मछली

प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है मछली। ओमेगा थ्री जैसा फायदेमंद ब्रेन टॉनिक और किसी में नहीं



मिलता। यह ब्रेन फंक्शन के साथ स्ट्रोक के खतरों को भी कम करती है। याददाश्त बढ़ाती है। हेल्दी ब्रेन व हार्ट के लिए सप्ताह में दो बार मछली खाएं।

नट्स

एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ विटामिन ई भी इनमें मौजूद है। नट्स हमारे शरीर में बी टाइप की कोशिकाओं का सृजन करते हैं, जो एंटीबायोजन बना कर हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती हैं। नट्स तनाव को झेलने की शक्ति भी देते हैं।

ल्यू बेरीज है सुपर ब्रेन फूड

रिसर्च बताती है कि बेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मस्तिष्क के लिए फायदेमंद हैं। यह फल फ्रॉइडिकल्स से होने वाले नुकसान से दिमाग को बचाता है, अल्जाइमर के खतरों को कम करता है। सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, मसल फंक्शन को ठीक करता है। न्यूरोट्रांसमीटर की सक्रियता बढ़ाता है।

सोशल सेक्टर में हासिल करें सफलता की ऊंचाईयां

मॉनीटरिंग और इवैल्यूएशन में बनाएं कैरियर

मॉनीटरिंग की प्रक्रिया वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट्स तथा प्रोग्राम्स से डाटा का सिस्टमेटिक कलेक्शन है ताकि भविष्य में प्रेक्टिस को सुधारा जाए, बाहरी जवाबदेही को सुनिश्चित बनाया जाए और जाने-पहचाने फैसले लिए जाएं। मॉनीटरिंग की गतिविधि एक ऐसा काम है जो किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है। मॉनीटरिंग उन प्रक्रियाओं तथा अनुभवों का दस्तावेजीकरण है जिनका इस्तेमाल आगे चलकर प्रोजेक्ट डिस्ट्रीकन मेकिंग में किया जाता है। मॉनीटरिंग से योजनाओं की प्रगति की जांच में भी सहायता मिलती है।



डाटा की पहचान में मिलती है मदद

इवैल्यूएशन से डाटा की पहचान में सहायता मिलती है जो रणनीतिक निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। इस तरह से यह प्रोजेक्ट्स के विभिन्न पहलुओं जैसे इसकी प्रसंगिकता, प्रभावी होना, निष्पत्ता, प्रभाव तथा सस्टेनेबिलिटी संबंधी समाधान खोजने में सहायता करती है।

जॉब एंड सैलरी

सोशल सर्विस एजीक्यूटिव के तौर पर जॉब कर सकते हैं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क को डिग्री के साथ प्रथम श्रेणी वाला ग्रेजुएट सोशल वर्क क्षेत्र में शुरुआती तौर पर 20 से 25 हजार रूपए प्रति माह की सैलरी पा सकता है। अनुभव बढ़ने के साथ-साथ सैलरी भी बढ़ती जाती है। सोशल सेक्टर में बने रहने के लिए आपके मन में समाज परिवर्तन की इच्छा होने के साथ ही समाज कल्याण संबंधी प्रोजेक्ट्स की समझ होनी चाहिए। साथ ही प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग और इवैल्यूएशन अच्छी तरह आना चाहिए।

सामाजिक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स से जुड़ा प्रमुख तत्व

मॉनीटरिंग एंड इवैल्यूएशन किसी भी सामाजिक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ प्रमुख तत्व है। सोशल सेक्टर में विकासवात्मक प्रोजेक्ट्स के लिए एम एंड ई स्टेज होल्डर्स के लिए सस्टेनेबिलिटी तथा स्यूटेबिलिटी संबंधी एक वृष्टि उपलब्ध करवाती है। सोशल सेक्टर के विकास के साथ ही कई सरकारी सेक्टर तथा गैर-सरकारी सेक्टरों द्वारा असांख्य स्कॉमों शुरू की गई हैं, जिनके लिए मॉनीटरिंग तथा इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को विशिष्ट जानकारी की जरूरत होती है।

भारत में 3.3 मिलियन के लगभग एनजीओ यानि गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं, जिनमें से 40 हजार विषय स्तर पर काम कर रहे हैं। सोशल सर्विस अडिस्ट्रेट या करने के इच्छुक लोग सोशल सर्विस प्रोफेशनल, सोशल सर्विस अडिस्ट्रेट या करने के साथ-साथ सैलरी भी बढ़ती जाती है। सोशल सेक्टर में बने रहने के लिए आपके मन में समाज परिवर्तन की इच्छा होने के साथ ही समाज कल्याण संबंधी प्रोजेक्ट्स की समझ होनी चाहिए। साथ ही प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग और इवैल्यूएशन अच्छी तरह आना चाहिए।

योग्यता...

इवैल्यूएशन व मॉनीटरिंग में विशिष्ट ट्रेनिंग उम्मीदवार को सोशल सेक्टर में जॉब प्राप्त करने में सहायक होती है। सोशल सेक्टर ज्वाइन करने के लिए मुख्य योग्यता है किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, साथ ही किसी भी विषय में मास्टर्स या मास्टर ऑफ सोशल वर्क। इसके लिए ग्रेजुएशन व सर्टीफिकेट कोर्स सोशल सेक्टर में काम करने के लिए सहायक होता है।

सुजनात्मक आलोचना, रचनात्मकता, नवाचार और समस्या सुलझाने के लिए अनिवार्य है।

चूँकि नेतृत्व में इन तीनों खूबियों की ही जरूरत होती है इसलिए लीडर्स को सिर्फ यही सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि वे आलोचना के प्रति सकारात्मक नजरिया रखें, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से इसकी तलाश भी करनी चाहिए। केवल सामान्य फीडबैक ही न मांगें, बल्कि लोगों-अधीनस्थों, समकक्षों, ग्राहकों से कहें कि वे आपके विचारों तथा नीतियों की कमियां बताएं। दरअसल, आलोचना विचारों को परखने और लोगों व टीमों को जवाबदेह रखने की उपयोगी नीति हो सकती है।



आलोचना के प्रति रखें सकारात्मक नजरिया

घटनाओं पर चिंतन...

हालात में फंसे हुए हैं तो आप अपने काम को पट्टी पर बनाए रखने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बेहतर है कि आप खुद के साथ सप्ताहिक मीटिंग करें। आप चाहे जितने व्यस्त हों, यह कोई विलासिता नहीं है। यह तो अनिवार्य है। हर सप्ताह एक घंटे तक एकांत में हाल ही में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चिंतन-मनन करें-संघर्ष, असाफल्यताएं, धुनाए गए अवसर, दुसरे के व्यवहार संबंधी अवलोकन, दुसरे से मिला फीडबैक। इस बारे में विचार करें कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी, क्या अच्छी तरह हुआ, क्या अच्छी तरह नहीं हुआ और भविष्य में क्या ज्यादा कारगर हो सकता है। इस मीटिंग को कभी रद्द न करें-यह बेहद महत्वपूर्ण है।

बेहतर श्रोता बनने के प्रयास...

नेतृत्व विशेषज्ञ बरसों से प्रबंधकों को प्रोत्साहित करते आ रहे हैं कि वे अपनी सुनने की क्षमता को बेहतर बनाएं। अच्छी तरह सुनने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वक्ता यह महसूस करे कि आप उसकी बात सुन रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। इसका अर्थ तो यह सुनिश्चित करना भी है कि आप कहीं गई बात को पूरी तरह समझ गए हैं। बेहतर श्रोता बनने के तीन युवावधि दिए जा रहे हैं।

गैर शब्दिक संकेतों पर गौर करें जिनसे पता चल सके कि वक्ता क्या नहीं कह रहा है। अनकही बात भी अक्सर कही गई बात जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। स्वयं के साथ नियमित मीटिंग्स करें ऐसी स्थिति में जब मुश्किल आर्थिक हालात में फंसे हुए हैं तो आप अपने काम को पट्टी पर बनाए रखने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बेहतर है कि आप खुद के साथ सप्ताहिक मीटिंग करें। आप चाहे जितने व्यस्त हों, यह कोई विलासिता नहीं है। यह तो अनिवार्य है। हर सप्ताह एक घंटे तक एकांत में हाल ही में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चिंतन-मनन करें-संघर्ष, असाफल्यताएं, धुनाए गए अवसर, दुसरे के व्यवहार संबंधी अवलोकन, दुसरे से मिला फीडबैक। इस बारे में विचार करें कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी, क्या अच्छी तरह हुआ, क्या अच्छी तरह नहीं हुआ और भविष्य में क्या ज्यादा कारगर हो सकता है। इस मीटिंग को कभी रद्द न करें-यह बेहद महत्वपूर्ण है।

समीक्षा करना भी जरूरी

किसी की बात सुनते समय आगे की सोचें और कल्पना करें कि वक्ता अब क्या कहने जा रहा है। सिर्फ शब्द ही न सुनें, बल्कि निष्कर्षों का अनुमान लगाने की कोशिश भी करें। कुछ देर ठहरें और मन ही मन बिंदुओं की समीक्षा करें।

रेसिपी आम का अचार



विधि
आम के स्ट्रिप्स और नमक को अच्छी तरह मिला लें। 1 घंटे के लिए रख दें। सारा आम का पानी नीचे निकाल लें। आम के स्ट्रिप्स, हींग, हल्दी पाउडर, सोंफ, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और सरसों का तेल को अच्छी तरह मिला लें। तुरंत परसें या फ्रिज में 4 दिनों तक संग्रह करें।

सामग्री

- 2 कप छिले हुए कच्चे आम, स्ट्रिप्स में कटे हुए
- 1/2 टी-स्पून हींग
- 1 टी-स्पून हल्दी पाउडर
- 2 टेबल-स्पून भुनी हुई सोंफ
- 2 टेबल-स्पून भुना हुआ जीरा
- 2 टेबल-स्पून लाल मिर्च पाउडर
- 1 टेबल-स्पून नमक
- 3 टेबल-स्पून सरसों का तेल

पनीर स्ट्रिंग अनियन पराठा



विधि
सभी सामग्री को एक गहरे बाउल में मिलाकर, जरूरत मात्रा में पानी का प्रयोग कर नरम आटा गूंध लें। आटे को 8 भाग में बॉट लें। थोड़े सूखे आटे का प्रयोग कर, आटे के प्रत्येक भाग को 125 मिमी के व्यास के गोल आकार में बेल लें। एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें और 1/4 टी-स्पून तेल का प्रयोग कर, पराठे के दोनों तरफ सुनहरे दाम पड़ने तक पका लें। और पराठे बना लें। तुरंत परसें।

सामग्री

- 1/2 कप कसा हुआ पनीर
- 1/2 कप बारीक कटी हुई हरी प्याज (सफेद भाग और पत्ते)
- 3/4 कप गेहूँ का आटा
- 1 टी-स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च
- नमक और ताजी पीसी हुई कालीमिर्च, स्वादानुसार
- गेहूँ का आटा, बेलने के लिए
- 2 टी-स्पून तेल, पकाने के लिए